वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report

1993-94

भारतीय डाक विभाग

Department of Posts, India

विषय सूची

भाग 1 :	वार्षिक रिपोर्ट (1992–93)	
	पुनरीक्षा	3
	संगठन	7
	डाक प्रचालन	9
	डाक वित्त	18
	मानव संसाधन	22
भाग 2 :	वार्षिक रिपोर्ट (1993–94)	25

CONTENTS

Part 1 :	**Annual Report (1992-93)**	
	Overview	**28**
	Organisation	**31**
	Postal Operations	**33**
	Postal Finance	**41**
	Human Resources	**45**
Part 2 :	**Annual Report (1993-94)**	**48**
	Statistical Supplements	**50**

Cover : Calcutta G.P.O., 125th Anniversary, 1993

भाग – 1

वार्षिक रिपोर्ट

1992–93

पुनरीक्षा

वर्ष 1992–93 में डाक विभाग आधुनिकीकरण के अपने कार्यक्रम को कार्यान्वित करता रहा। उसका यह आधुनिकीकरण कार्यक्रम नवीनतम प्रौद्योगिकीय विकास, विभाग में उपलब्ध मानव और वित्तीय संसाधनों के अनुरूप रहा। यह प्रक्रिया नियमित और सशक्त रही, जिसके फलस्वरूप विभाग के अनेक विंगों का आधुनिकीकरण हुआ। समीक्षाधीन वर्ष की विशिष्ट बातें हैं — बम्बई में ऑटोमेटेड मेल प्रोसेसिंग सेंटर की सफल शुरुआत और डाकघरों में कम्प्यूटरीकृत बहुद्देशीय काउंटर मशीनों की बढ़ी हुई आपूर्ति। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 7.12.93 से देश भर में डाक हड़ताल आरम्भ हुई, जो संचार राज्य मंत्री के साथ यूनियन के प्रतिनिधियों की बैठक के बाद 11.12.93 को समाप्त हुई। इस पुनरीक्षा का केन्द्र बिन्दु है — कार्य और प्रबंध तकनीक में परिवर्तन, डाक की वित्तीय स्थिति और मौजूदा प्राथमिकताएं।

डाक मशीनीकरण

विभाग का मूल कार्य परंपरागत तौर पर डाक का संग्रह, छंटाई, प्रेषण और वितरण रहा है। इनमें से अधिकांश प्रचालन मैनुअल है। तथापि बम्बई में 30 बार कोडिंग डेस्कों वाली दो पत्र छंटाई मशीनें लगाकर डाक छंटाई के आधुनिकीकरण और मशीनीकरण के क्षेत्र में एक शुरुआत की गई जिससे इस अत्यंत शहरीकृत क्षेत्र की डाक की छंटाई में तेजी आ गई। मद्रास, दिल्ली, कलकत्ता और बेंगलूर में भी इसी प्रकार की परिष्कृत डाक छंटाई प्रणाली की व्यवस्था करने की योजना है।

काउंटर मशीनीकरण

7 शहरों के 22 डाकघरों में 102 पी सी आधारित बहुद्देशीय काउंटर मशीनों की आपूर्ति की गई। 750 और मशीनों के लिए आर्डर दिए गए हैं और आशा है कि इनकी आपूर्ति भी शीघ्र हो जाएगी।

डाक उपस्कर

डाक–टिकटों की गुणवत्ता में सुधार के लिए 25,000 हस्त मुहरों के निर्माण के आदेश आर्डिनेंस फैक्ट्री आर्गनाइजेशन को दिए गए हैं और इनकी आपूर्ति शुरु हो गई है। विभाग ने 270 डाक–टिकट विरूपण मशीनों की आपूर्ति के लिए आर्डर दिया है जिनकी आपूर्ति अपेक्षाकृत बड़े और प्रमुख डाकघरों में की जाएगी।

स्पीड पोस्ट

स्पीड पोस्ट सेवा को आगे संघटित कर दिया गया है तथा विभाग के उद्देश्य के अनुकूल बना दिया गया है। घाना, हंगरी, मलेशिया, मोरक्को, गुयाना, युगांडा, डेनमार्क, ईरान, मेक्सिको, नाइजर, पनामा, पपुआ न्यू गिनी तथा जैरे – इन 13 देशों के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट संपर्क स्थापित किए गए।

स्पीड पोस्ट सुरक्षित और शीघ्र वितरण सुनिश्चित करता है। इस संबंध में

सेवा के प्रभावशाली रिकार्ड को ध्यान में रखते हुए विलम्ब से वितरण के मामलों में दिनांक 17.8.1992 से स्पीड पोस्ट शुल्क की पूरी राशि लौटाने की अनुमति दी गई है।

स्पीड पोस्ट परियात में 38% तथा राजस्व में 45% की वृद्धि हुई।

भारतीय डाकघर अधिनियम की पुनरीक्षा

देश में डाक प्रणाली को शासित करने वाले अधिनियम का 1960 से पुनरीक्षण और संशोधन किया जा रहा है। 1983 और 1986 में दो विधायी प्रयास किए गए। 1986 का विधेयक यद्यपि संसद के दोनों सदनों द्वारा पास कर दिया गया था, किन्तु इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा 1990 में पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया। इसी बीच इसमें आगे और परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस की गई, अतः 1992 में एक समिति गठित की गई जिसकी शर्तें निम्न प्रकार से हैं :

अन्य बातों के साथ-साथ इस अधिनियम के निम्नलिखित पक्षों की विशेष रूप से जांच करना :-

(i) हाल के वर्षों में देश में डाक द्वारा संचार में प्रगति और भविष्य में संभावित प्रवृत्तियां तथा डाकघर को उनसे मिलने वाली चुनौतियां;

(ii) अंतर्राष्ट्रीय डाक प्रणाली में विकास और डाकघर पर आने वाले उत्तरदायित्व;

(iii) अधिनियम की सीमाओं के कारण डाकघर द्वारा फिलहाल अनुभव की गई व्यावहारिक कठिनाइयां; तथा

(iv) बढ़ती हुई उपभोक्ता संरक्षण प्रवृत्तियां, सेवाओं के विस्तार के साथ इसकी अनुकूलता, वे परिस्थितियां जिनके अंतर्गत अपेक्षाकृत कम डाक शुल्क और फीस पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं - इन सबके संदर्भ में कानूनी देयता, जिसे डाकघर को अपनी सेवाओं के लिए स्वीकार करना चाहिए;

तथा इस अधिनियम में सुधार करने के लिए सुझाव देना और एक उचित मसौदा विधान प्रस्तुत करना।

डाक सेवा बोर्ड ने समिति की रिपोर्ट की जांच की तथा सभी सिफारिशों पर विचार किया। अब रिपोर्ट पर आधारित मसौदा विधान को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

एकमुश्त डाक केन्द्र और पहले से छंटी हुई डाक पर छूट

प्रचालनात्मक नीति में एक नया आकर्षण एकमुश्त भेजी गई पंजीकृत और अपंजीकृत डाक का निपटान करने के लिए बड़े-बड़े शहरों में एकमुश्त डाक केन्द्रों की स्थापना करने का निर्णय है। इस विशेष यूनिट का प्रमुख उद्देश्य कारपोरेट सेक्टर से शेयर और डिबेंचर सर्टिफिकेट्स, रिफंड आर्डर्स और डिविडेंड सर्टिफिकेट्स, रिफंड आर्डर्स और डिविडेंड वारंट्स तथा अन्य पत्र-डाक की डाक लेन-देन में सुविधा प्रदान करना है, किन्तु यह सुविधा दूसरों को भी प्रदान की जाती है। जब 10,000 या इससे अधिक अपंजीकृत पत्र और 250 या इससे अधिक पंजीकृत पत्र किसी एक प्रेषक द्वारा भेजे जाते हैं तो इन्हें एकमुश्त डाक समझा जाएगा। एकमुश्त डाक केन्द्रों में केवल पहले से छांटी गई डाक स्वीकार की जाएगी। विभाग की अपेक्षा के अनुसार पहले से छांटी गई डाक से प्रेषक को डाक-शुल्क में 2% की छूट मिलेगी। इसके अतिरिक्त फ्रैंकिंग मशीन के प्रयोक्ता को पहले से ही दी जाने

वाली छूट भी उन्हें प्राप्त होगी। पंजीकृत वस्तुओं के लिए यह छूट पंजीकरण शुल्क में भी दी जाएगी।

कार्य–निष्पादन सूचक

एक महत्वपूर्ण प्रबंध प्रयोग जो 1992–93 में फलीभूत हुआ, वह था – प्रत्येक सर्किल के प्रगामी रूप से निष्पादित उसके अपने कार्य तथा अन्य सर्किलों की तुलना में उसके कार्य। इस योजना के लिए आवश्यक है – विकास, प्रचालन, वित्त और कार्मिक कल्याण जैसे सभी मूल पक्षों सहित डाक सर्किल का प्रबंध मूल्यांकन। प्रत्येक सूचक के माध्यम से पता लगाए गए कार्य–निष्पादन से विशिष्ट क्षेत्रों में विभिन्न प्रबंध कार्यक्रमों की योजना बनाने में सर्किल अध्यक्ष को अत्यावश्यक प्रबंध निवेश प्राप्त होता है।

डाक नेटवर्क का विस्तार

आठवीं योजना के लक्ष्यों के संदर्भ में डाक नेटवर्क के विस्तार के लिए पहाड़ी, रेगिस्तानी, जनजातीय क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिए जाने का प्रस्ताव है। योजना के दौरान जनजातीय, पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में खोले जाने वाले अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों का लक्ष्य 1500 था। वर्ष 1992–93 के दौरान लक्ष्य से अधिक अतिरिक्त विभागीय डाकघर खोले जा चुके थे। वर्ष 1993–94 के लिए 600 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 100 शाखा उपडाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनमें से 230 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 20 विभागीय उपडाकघर जनजातीय क्षेत्रों में खोले जाने हैं। अगस्त, 1993 तक 358 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने के मंजूरी आदेश जारी कर दिए गए हैं।

विपणन

विपणन डिवीजन में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे जा सकते हैं। भारतीय डाक प्रशासन अच्छे जन संपर्क, लोक शिक्षा और सूचना प्रसार में पूर्णतः विश्वास रखता है। जब जन चेतना हो और उपभोक्ता की मनोवृत्ति सकारात्मक हो तब विपणन प्रयास किफायती होते हैं।

इस पृष्ठभूमि में विपणन डिवीजन ने एक व्यापक मिश्रित छवि योजना प्रतिपादित की तथा समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के माध्यम से चलाये गये ग्राहक अनुकूलन अभियान से सामान्यतः प्रशंसात्मक जन प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। सेवाओं को ग्राहक की आवश्यकता के अनुकूल बनाने के लिए स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा विभिन्न विपणन सर्वेक्षण किए गए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारतीय डाक प्रशासन ने एशियाई प्रशांत डाक यूनियन की कार्यकारी परिषद् की वार्षिक बैठक और एशियाई प्रशांत डाक प्रशिक्षण केन्द्र शासी बोर्ड की 22वीं बैठक की मेजबानी करके अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध और मजबूत कर लिये। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री के. आर. नारायणन ने 17 सितम्बर, 1992 को एशियाई प्रशांत डाक संघ की कार्यकारिणी परिषद् की विचार- गोष्ठी का उद्घाटन किया।

विश्व डाक संघ की डाक अध्ययन सलाहकार परिषद् (सी सी पी एस) का वार्षिक सत्र 12 अक्तूबर से 23 अक्तूबर, 1992 तक बर्न में आयोजित हुआ। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डाक विभाग के तत्कालीन सचिव श्री एल. डी. बोनल ने किया।

भारत ने डाक पर भारत–फ्रांस कार्यकारी ग्रुप की एक बैठक आयोजित की। फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उनके डाक व दूरसंचार मंत्री ने किया।

वाराणसी क्षेत्र के निर्यातकों को अब एक नई सुविधा प्राप्त हो गई है। बाबतपुर कार्गो काम्प्लेक्स में एक एक्सपोर्ट एक्सटेंशन पोस्टल विंडो खोला गया है।

दो भारतीय डाक विशेषज्ञों ने डाक प्रेषण मानदंडों और रियायती डाक दर पर सार्क के लिए अध्ययन किए।

फिलैटली

देश में फिलैटेलिस्टों की बढ़ती हुई संख्या की रुचि को पूरा करने के लिए विभाग प्रमुख डाकघरों में 50 फिलैटली ब्यूरो और 174 फिलैटली काउंटर चलाता है। कर्नाटक, राजस्थान और केरल सर्किलों में राज्य स्तरीय फिलैटली प्रदर्शनियां आयोजित की गई। डाक विभाग ने ग्रेनाडा, शिकागो और कुआलालाम्पुर में तीन अंतर्राष्ट्रीय फिलैटली प्रदर्शनियों मे भाग लिया।

कारपोरेट आइडेंटिटी

डाकघर के जन संपर्क के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय प्रगति कारपोरेट नामशैली को स्वीकार करना था। 9 अक्तूबर, 1993 को यह नामशैली औपचारिक रूप से लागू की गई। इसमें पोस्टल लाल रंग में एक जोड़ा पंख दर्शाए गए है, जिसका शीर्षक है "भारतीय डाक" और "इंडिया पोस्ट"।

वित्त

पुनरीक्षाधीन वर्ष (1992–93) के दौरान कुल राजस्व 1073.90 करोड़ रु. था (इसमें 126.03 करोड़ रु. की वृद्धि हुई), जबकि 1991–92 में इसकी आय 947.87 करोड़ रु. थी। पिछले वर्ष के 1162.15 करोड़ रु. के व्यय की तुलना में इस वर्ष का कुल कार्यकारी व्यय 1165.71 करोड़ रु. था। 1992–93 के संशोधित प्राक्कलन में दर्शाया गया अनुमानित व्यय 1149.36 करोड़ रुपये था।

कुल व्यय - राजस्व अंतर पिछले वर्ष के 214.28 करोड़ रु. से घटकर 91.81 करोड़ रु. रह गया। राजस्व के अपेक्षाकृत अधिक संग्रह, लीकेज बंद होने, बेहतर वित्तीय प्रबंध और कड़ी अर्थव्यवस्था के द्वारा 120 करोड़ रु. से अधिक का अंतर कम किया जा सका।

संगठन

तत्कालीन डाक–तार विभाग का विभाजन करने के पश्चात् जनवरी, 1985 में डाक विभाग का सृजन किया गया था। यह संचार मंत्रालय का एक अंग है। विचाराधीन वर्ष के दौरान विभाग श्री सुखराम, संचार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के अधीन कार्य करता रहा।

मुख्यालय

विभाग की प्रबंध व्यवस्था डाक सेवा बोर्ड करता है। बोर्ड के अध्यक्ष डाक विभाग के सचिव और महानिदेशक (डाक) भी हैं। बोर्ड के तीन सदस्य हैं जिन्हें प्रचालन, विकास और कार्मिक के कार्य सौंपे गए हैं। इसके अतिरिक्त एक वित्तीय सलाहकार भी हैं। बोर्ड की सहायता के लिए एक सचिव हैं जो वरिष्ठ उपमहानिदेशक (निरीक्षण और दक्षता ब्यूरो) भी हैं। यह बोर्ड डाक महानिदेशालय में अठारह उप महानिदेशकों की सहायता से देश की डाक सेवाओं के प्रबंध का निर्देशन और पर्यवेक्षण करता है।

सर्किल

विभाग के प्रचालन दायित्वों को निभाने के लिए 19 डाक सर्किल हैं। एक सर्किल में एक अथवा एक से अधिक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र होते हैं। सर्किल के अध्यक्ष मुख्य पोस्टमास्टर जनरल होते हैं। सर्किलों को सामान्यतः क्षेत्रों में बांटा गया है। इन क्षेत्रों में फील्ड यूनिटों के अनेक ग्रुप हैं जिन्हें डिवीजन कहा जाता है। क्षेत्र में मुख्य पोस्टमास्टर जनरल को उच्चस्तरीय प्रबंध सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में एक पोस्टमास्टर जनरल है।

सर्किलों के अतिरिक्त बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में पोस्टमास्टर जनरल के स्तर के नियंत्रकों के अधीन क्षेत्रीय डाक योजना इकाइयां हैं। नियंत्रक डाक प्रचालनों की योजना और नियंत्रण में बेहतर व्यावसायिकता लाते हैं। सर्किल में मेल डिवीजन, स्टोर डिपो, स्टैम्प डिपो और मेल मोटर सेवा जैसी अन्य कार्यात्मक डिवीजन और यूनिटें भी हैं।

भारतीय डाकघरों की श्रेणियां इस प्रकार हैं–मुख्य डाकघर, उपडाकघर और शाखा डाकघर। शाखा डाकघर प्रायः अतिरिक्त विभागीय डाकघर हैं तथा ये ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। अधिकतर उप डाकघर विभागीय हैं तथा ये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्थित हैं। मुख्य डाकघरों को उनके कार्यभार और कर्मचारी क्षमता के अनुसार पांच श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें मुख्य डाकघर, बम्बई और मुख्य डाकघर, कलकत्ता सबसे बड़े हैं। इनके बाद मद्रास, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलूर, कानपुर, लखनऊ और देश के अन्य बड़े शहरों में स्थित मुख्य डाकघरों का स्थान है।

सेना डाक सेवा के अध्यक्ष मेजर जनरल होते हैं, जिन्हें अपर महानिदेशक, सेना डाक सेवा का पदनाम दिया गया है। उन्हें मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, सेना डाक सेवा सर्किल भी कहा जाता है। अधिकांश अधिकारी और मेजर जनरल सहित अन्य पद सिविल डाक सेवा से लिए जाते हैं।

स्थिति

31 मार्च, 1993 की स्थिति के अनुसार, डाक सेवा बोर्ड में श्री एस. के. पार्थसारथि, सचिव (डाक), महानिदेशक, डाक और अध्यक्ष, डाक सेवा बोर्ड, श्री एम.एस. राघवन, सदस्य (कार्मिक), श्री टी. ई. रमन, सदस्य (प्रचालन) और श्री एस. आर. फारूकी, सदस्य (विकास) थे। श्री जी. एस. राजामणि, डाक विभाग के संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार हैं तथा बोर्ड के स्थाई आमंत्रित सदस्य हैं। श्री बि. परब्रह्म वरिष्ठ उप महानिदेशक (आई एंड ई बी) तथा सचिव, डाक सेवा बोर्ड थे। इस समय श्री एस. पी. राय, सदस्य (कार्मिक) हैं जिन्होंने 30 सितम्बर, 1993 को श्री एम. एस. राघवन के सेवानिवृत्त होने पर यह पदभार ग्रहण किया था।

अंतर्राष्ट्रीय डाक संबंध

डाक विभाग ने 15 से 21 सितम्बर, 1992 तक नई दिल्ली में एशियाई प्रशांत डाक यूनियन (ए पी पी यू) की कार्यकारिणी परिषद् की वार्षिक बैठक और एशियाई प्रशांत डाक प्रशिक्षण केन्द्र शासी बोर्ड की 22वीं बैठक की मेजबानी की। भारत सहित बीस सदस्य देशों के प्रतिनिधि और

विश्व डाक संघ (यू पी यू) तथा चार अन्य डाक प्रशासनों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। 17 सितम्बर को भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री के. आर. नारायणन ने ए पी पी यू की कार्यकारिणी परिषद् की बैठक का उद्घाटन किया। विचार-विमर्श का मुख्य विषय था-एशियाई-प्रशांत क्षेत्र में डाक सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के उपाय और साधन। उपभोक्ता संतुष्टि, विपणन के अनुकूल उपलब्धता और प्रशिक्षण जैसे विषय बैठक में विचार-विमर्श के केन्द्र बिन्दु थे। भारत ने ए पी पी यू की तकनीकी सहयोग और सहायता की स्थाई समिति की बैठक की अध्यक्षता की।

विश्व डाक संघ की डाक अध्ययन सलाहकार परिषद् (सीसीपीएस) का वार्षिक सत्र 12 अक्तूबर से 23 अक्तूबर, 1992 तक बर्न, स्विटजरलैंड में आयोजित हुआ। एक प्रतिनिधिमंडल ने इस बैठक में भाग लिया। इस प्रतिनिधिमंडल में श्री एल. डी. बोनल, सचिव, डाक विभाग, श्री एस. के. पार्थसारथि, सदस्य (कार्मिक) और श्री आर. यू. एस. प्रसाद, उप महानिदेशक (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) शामिल थे। इस सी सी पी एस सत्र की अभिन्न अंग थीं-चार विचार-गोष्ठियां, जिनके विषय थे, "मानव संसाधन", "अनुसंधान और विकास", "ई एम एस" और "डाक विपणन"।

फ्रांसीसी डाक प्रशासन के एक प्रतिनिधिमंडल ने फ्रांस के डाक व दूरसंचार मंत्री के साथ भारत का दौरा किया। 24.11.92 को डाक पर भारत-फ्रांस कार्यकारी ग्रुप की एक बैठक आयोजित हुई। संचार मंत्री और फ्रांस के मंत्री ने डाक और दूरसंचार क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग के एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। डाक क्षेत्र में सहयोग के लिए प्रोटोकॉल में जिन क्षेत्रों का पता लगाया गया था, वे थे-डाक सेवाओं का आधुनिकीकरण, स्पीड पोस्ट, प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय डाक। यह भी निर्णय लिया गया कि समझौते के एक नए ज्ञापन द्वारा डाक क्षेत्र में दो देशों के बीच सहयोग बढ़ाना परस्पर लाभप्रद होगा।

दिनांक 1.12.92 से तेरह और देशों में अंतर्राष्ट्रीय ई एम एस नेटवर्क का विस्तार किया गया है। इसके परिणामस्वरूप अब 61 देशों के साथ भारत का ईएमएस संपर्क स्थापित हो गया है। वाराणसी क्षेत्र से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की बुकिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए वाराणसी के बाबतपुर कार्गो कॉम्प्लेक्स उप-डाकघर में एक एक्सपोर्ट एक्सटेंशन विंडो खोला गया है।

डाक प्रचालन

प्रस्तावना

डाक प्रचालन का प्रायः एक ही कार्य समझा जाता रहा है; पत्रों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर वितरण करना। वास्तव में यह पंजीकरण, मनीआर्डर, स्पीड पोस्ट, डाक-टिकटों की बिक्री, पोस्टल ऑर्डर आदि जैसे कार्यों के अंतः संबंधों की बहुरंगी कड़ी है। इस प्रचालन की सफलता अकसर परिवहन क्षेत्र की दूसरी एजेंसियों जैसे एयरलाइंस, रेलवे, रोडवेज, शिपिंग आदि पर निर्भर करती है। डाकघर दूसरे मंत्रालयों/विभागों जैसे बचत बैंक और डाक जीवन बीमा आदि के कार्य भी करता है, जो एजेंसी कार्य के नाम से जाने जाते हैं।

डाक नेटवर्क का विस्तार

जहां तक डाकघरों की संख्या का संबंध है, विश्व डाक प्रणाली में भारत का प्रमुख स्थान है, एक ओर जहां इसका श्रेय इस देश की विशालता और इसकी विशाल जनसंख्या को है, वहीं दूसरी ओर इसका श्रेय स्वतंत्रता से लेकर अब तक सरकार द्वारा डाक नेटवर्क को सामाजिक एकता तथा आर्थिक विकास और ग्रामीण पुनरुद्धार के एक साधन के रूप में विकसित करने के सजग प्रयासों को भी है। डाक-संचार के विस्तार के आधारभूत उद्देश्य की पूर्ति करने के अलावा, डाक सेवाओं के विस्तार ने सरकार के सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति - जैसे विकास, साक्षरता का प्रसार, रोजगार, लघु बचत को प्रोत्साहन तथा पिछड़े इलाकों में उद्योगों की स्थापना में भी महत्वपूर्ण योग दिया है। सातवीं योजना के अंत तक राष्ट्रीय डाक नेटवर्क में 1,47,236 डाकघर शामिल हैं, जिनमें से 16,249 डाकघर शहरी क्षेत्रों में तथा 1,30,987 डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में थे। 31.3.93 की स्थिति के अनुसार देश में 1,52,037 डाकघर थे, जिनमें से 16,283 शहरी क्षेत्रों में तथा 1,35,754 ग्रामीण क्षेत्रों में थे। 1991 की गणना के अनुसार एक डाकघर औसतन 21.6 वर्ग कि. मी. क्षेत्र और 5553 व्यक्तियों को सेवा प्रदान करता था।

योजना आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दौरान 500 विभागीय उपडाकघर (वि.उ.डा.) तथा 3000 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर (अ.वि.शा.डा.) खोलने के लक्ष्य को मंजूरी दी है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में पहाड़ी, रेगिस्तानी तथा जनजातीय क्षेत्रों में डाक नेटवर्क के विस्तार हेतु विशेष बल दिए जाने का प्रस्ताव है। योजना अवधि के दौरान जनजातीय उप-योजना के तहत 1500 अ.वि.शा.डा. खोलने का प्रस्ताव है।

वर्ष 1992-93 के दौरान 600 अ.वि.शा.डा. तथा 100 वि.उ.डा. के लक्ष्य की तुलना में क्रमशः 635 अ.वि.शा.डा. तथा 116 विभागीय उप डाकघरों को मंजूरी प्रदान की गई।

डाकघरों की संख्या

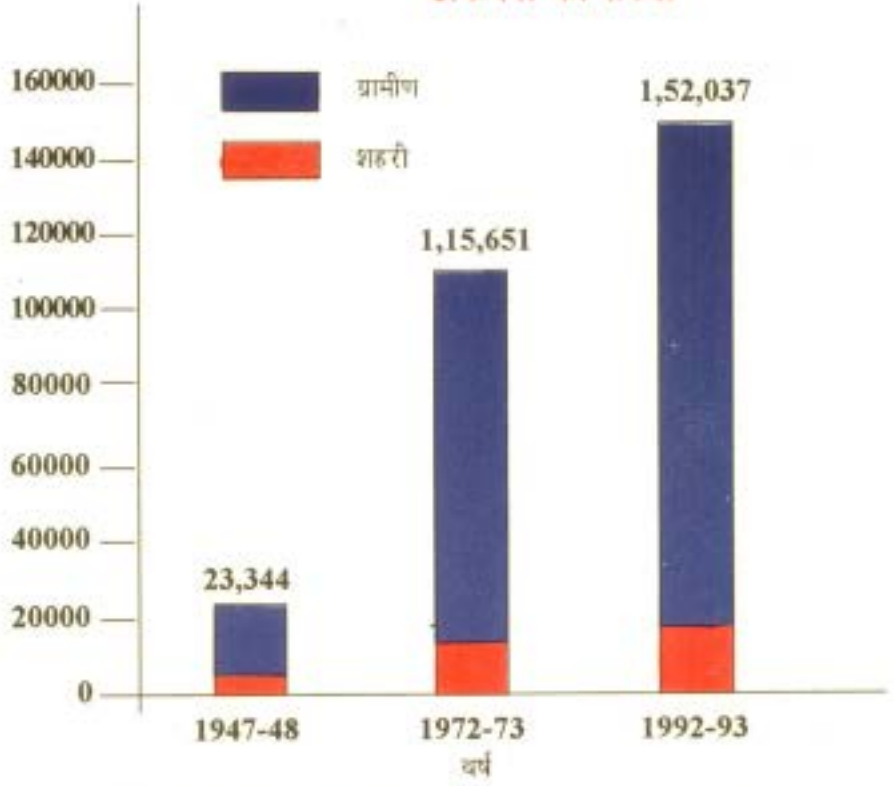

सेवाएं

प्रदत्त की जाने वाली डाक सेवाएं

डाक सेवाएं
जैसे पत्र, इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :
लिफ़ाफ़े, लेटर-कार्ड,
पोस्टकार्ड,
बुक पैकेट,
न्यूज पैकेट,
न्यूजपेपर,
पैकेट पार्सल

इनका वर्गीकरण निम्नानुसार किया गया है:
साधारण डाक
पोस्टिंग सर्टिफाइड
आर्डीनरी मेल
रजिस्ट्रेशन
वैल्यूपेएबल
बीमा
स्पीड पोस्ट

धन अंतरण सेवाएं
जैसे मनीआर्डर
पोस्टल आर्डर
अन्य सेवाएं
अर्थात् बचत बैंक
डाक जीवन बीमा
तार
टेलीफोन पब्लिक कॉल आफिसेज
टेलीफोन रेवेन्यू कलेक्शन
पासपोर्ट आवेदन-पत्र
केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट

1983–84 से डाक परियात
(राजस्व में समायोजित)

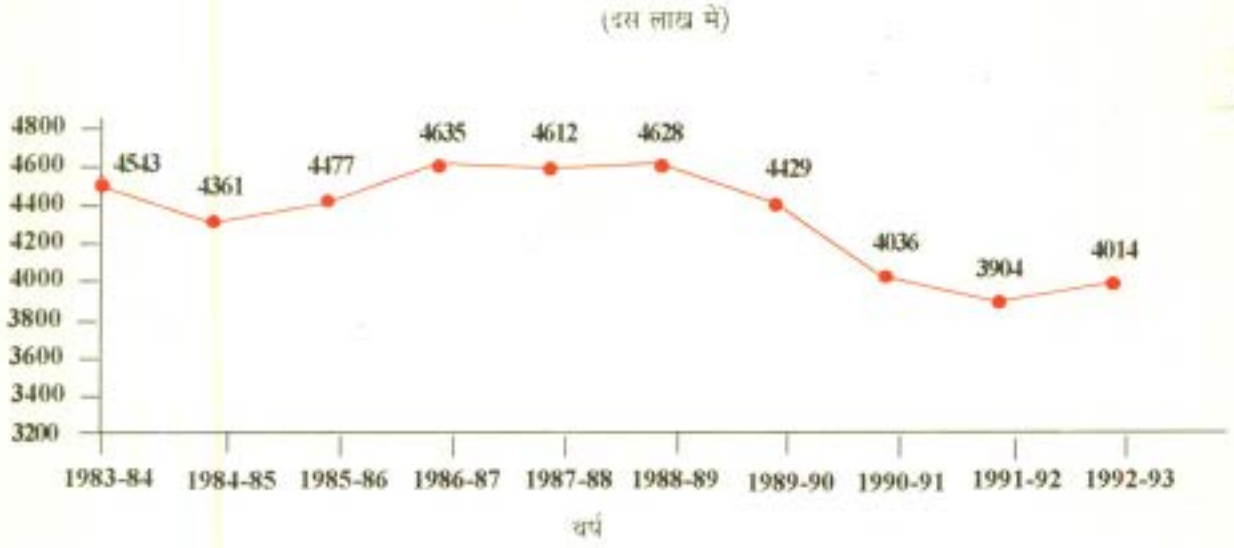

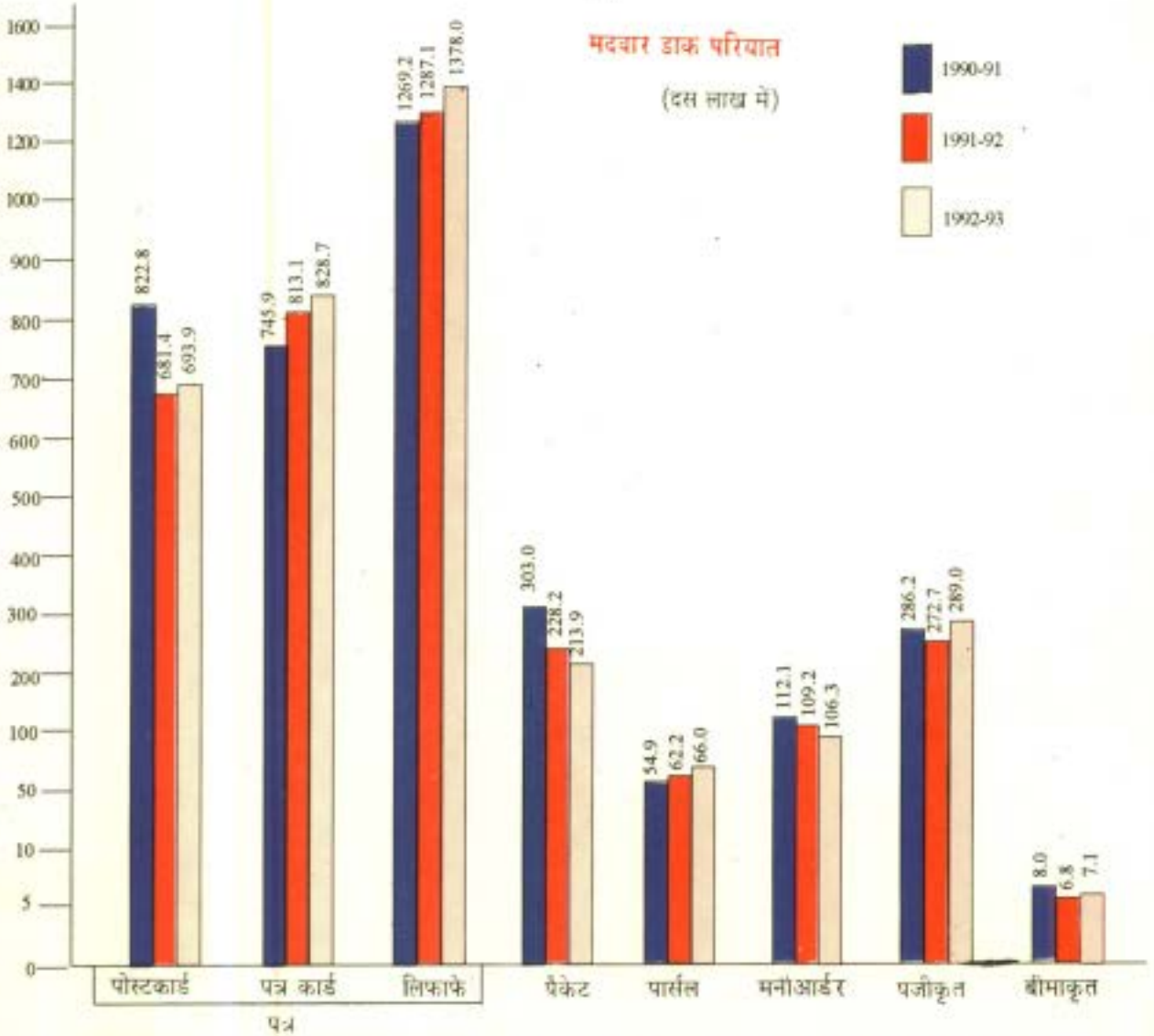

डाक मात्रा

वर्ष 1992–93 के दौरान कुल 3255 मिलियन गैर–पंजीकृत अंतर्देशीय डाक मदों का निपटान किया गया, जिसमें 2835 मिलियन पत्र, 378 मिलियन पैकेट तथा 42 मिलियन पार्सल सम्मिलित हैं। पंजीकृत अंतर्देशीय डाक की संख्या 314 मिलियन है। इस अवधि के दौरान डाक विभाग ने 105.3 मिलियन मनीआर्डरों का प्रेषण किया, जिनकी कुल राशि 29124 मिलियन रुपए थी।

स्पीड पोस्ट

1 दिसंबर, 1992 से 13 अन्य देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट संपर्क स्थापित किए गए जिनके नाम इस प्रकार हैं–घाना, हंगरी, मलेशिया, मोरक्को, गुयाना, युगांडा, डेनमार्क, ईरान, मेक्सिको, नाइजर, पनामा, पपुआ न्यू गिनी, गुयाना तथा जैरे।

अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क कनैक्शनों वाला एक नया स्पीड पोस्ट केन्द्र हावड़ा में दिनांक 1.6.1992 को खोला गया, इसे मिलाकर राष्ट्रीय केंद्रों की कुल संख्या बढ़कर 62 हो गई (6 एक्सटेंशन काउंटरों सहित), प्वाइंट टू प्वाइंट स्पीड पोस्ट सेवा के अन्तर्गत युग्म–स्टेशनों की संख्या 349 से बढ़कर 737 हो गई। स्पीड पोस्ट परियात में 38 प्रतिशत तथा राजस्व में 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

विलंब से वितरण के मामलों में 17.8.92 से स्पीड पोस्ट प्रभारों की संपूर्ण राशि की वापसी की योजना आरंभ की गई।

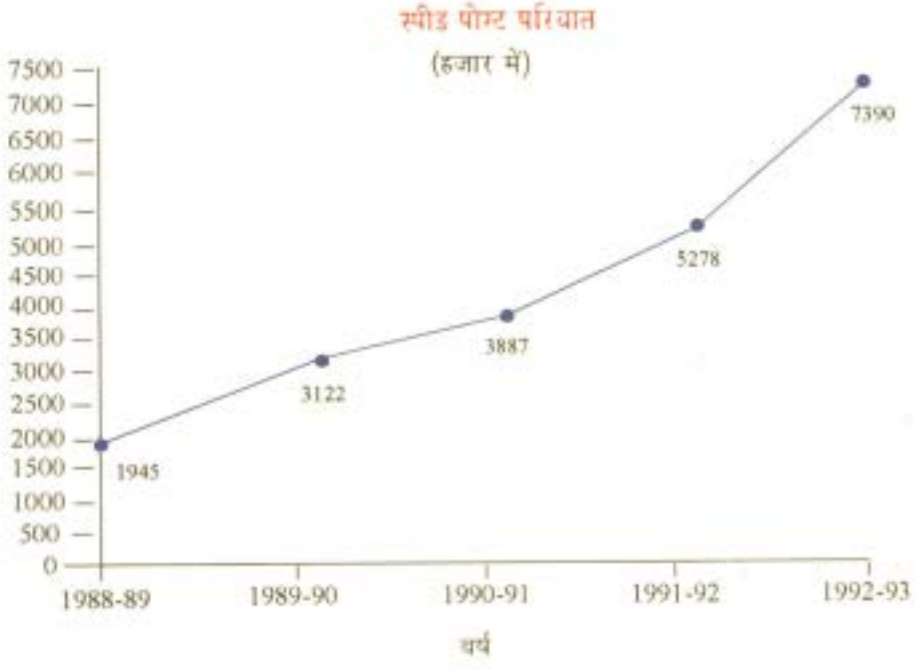

डाक प्रचालन

जहाँ एक ओर विभाग महानगरों में डाक पारेषण प्रणाली का आधुनिकीकरण कर रहा है, वहीं दूसरी ओर यह देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में डाक नेटवर्क को सुधारने के लिए भी समान रूप से प्रतिबद्ध है। हाल ही में विभाग ने रक्षा मंत्रालय के साथ पोर्ट ब्लेयर से कार निकोबार तक भारतीय वायुसेना की उड़ानों द्वारा डाक ले जाने और लाने के लिए एक समझौता किया है। इससे द्वीपसमूह के सुदूर के द्वीपों को तथा इन द्वीपों से होने वाले डाक-संचालन में तेजी आई है।

कठिनाइयों का पता लगाने तथा उनके समाधान के लिए विविध डाक अनुवीक्षण पद्धतियों को सुधारा गया है।

प्रौद्योगिकी अधिष्ठापन

आधुनिक प्रौद्योगिकी का आगमन, विशेष रूप से कम्प्यूटर द्वारा सूचना-प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक डेटा प्रोसेसिंग में कम्प्यूटर द्वारा लाए गए सुधार, एक सार्वभौमिक घटना बन चुके हैं और समूचे विश्व में इसे समय की मांग के रूप में देखा जा रहा है। डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए जिन क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया है, वे हैं काउंटर-यंत्रीकरण, डाक-यंत्रीकरण, उपग्रह के माध्यम से इलेक्ट्रानिक मनी ट्रान्सफर, यांत्रिक-उपस्कर तथा सहायक सामग्री और बचत बैंक, डाक जीवन बीमा तथा चुनिंदा लेखा-प्रचालनों का कम्प्यूटरीकरण।

मेल मोटर सेवा

वर्ष 1992-93 के दौरान विभागीय मेल मोटर इकाइयों ने देश के 90 स्टेशनों पर कार्य किया। डाक लाने-ले जाने में कुशलता लाने के उद्देश्य से पुराने वाहनों के स्थान पर 124 नए वाहन लाए गए। मेल मोटर के बेड़े की कुल संख्या 1103 थी और इसने 1.76 करोड़ कि.मी. की कुल दूरी तय की।

अवकाश दिवसों पर डाक-वितरण

पहले, डाकघर पूर्ण रूप से अदा की गई अपंजीकृत डाक का वितरण सभी डाकघर अवकाश-दिवसों को किया करते थे। 1974 में इसे घटाकर तीन राष्ट्रीय अवकाश-दिवसों तक सीमित कर दिया गया। 1982 में किफ़ायती उपाय के रूप में अवकाश-दिवसों पर डाक वितरण पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। तथापि, मध्यवर्ती वर्षों के अनुभव के आधार पर इसमें थोड़ी रियायत देना आवश्यक समझा गया। जब अवकाश दिवस लगातार आते थे तो डाक, जनता को दो या उससे अधिक दिन तक वितरित नहीं की जा पाती थी, जिसके कारण जनता के साथ-साथ पोस्टल-स्टाफ को भी असुविधा होती थी, क्योंकि उन्हें आगामी कार्य-दिवस को अपेक्षाकृत अधिक डाक को निपटाना पड़ता था। सितम्बर, 1992 में पूर्ण रूप से भुगतान की गई अपंजीकृत डाक का, डाक अवकाश-दिवसों को एक बार वितरण आरंभ करने के आदेश जारी किए गए थे, इन अवकाश-दिवसों में राष्ट्रीय अवकाश दिवस तथा रविवार सम्मिलित नहीं थे। इससे अब यह सुनिश्चित हो गया है कि डाक का वितरण एक साथ दो दिन से अधिक की अवधि तक लंबित नहीं रहेगा।

दिल्ली में कारपोरेट डाकघर

वर्ष 1992 में पहले से छंटी हुई डाक को, जो एकमुश्त भेजी जाती है, संसाधित करने के लिए दिल्ली में दो एकमुश्त डाक केंद्र खोले गए थे। इसके उपरांत बंबई में तथा अन्यत्र भी ऐसे केंद्र खोले गए।

पासपोर्ट आवेदन-पत्र

चुनिंदा डाकघरों पर दिनांक 1.11.92 से पासपोर्ट के आवेदन-पत्रों की बिक्री आरंभ की गई थी। सभी प्रधान डाकघर तथा लगभग एक हजार चुनिंदा उपडाकघर अब ये आवेदनपत्र बेचते हैं।

केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकटें

दिनांक 1.1.93 से केंद्रीय भर्ती शुल्क टिकटों की बिक्री सभी विभागीय डाकघरों में बढ़ा दी गई थी।

फिलैटली

दिनांक 1.4.92 से 31.3.93 तक 37 विशिष्ट/स्मारक डाक-टिकटें जारी की गईं। इनमें चार-चार टिकटों के तीन सेट तथा दो टिकटों के दो सेट शामिल थे। गुलाबी तथा हलके सलेटी रंग के अंतर्देशीय पत्र शुरू किए गए। ये हलके नीले-हरे अंतर्देशीय पत्रों के अतिरिक्त हैं, जो पहले ही उपलब्ध हैं। एक नवीन प्रयोग हलके "सी ग्रीन" और हलके नीले पोस्टकार्डों की शुरूआत थी।

दिनांक 31.3.93 की स्थिति के अनुसार देश में 50 फ़िलैटेलिक ब्यूरो और 174 फ़िलैटेलिक काउंटर कार्य कर रहे थे। वर्ष के दौरान राज्य स्तर की निम्नलिखित फ़िलैटेलिक प्रदर्शनियां आयोजित की गईं-

मैसूर, कर्नाटक सर्किल में दिनांक 11.9.92 से 13.9.92 तक कार्नापैक्स-92

जयपुर, राजस्थान सर्किल में दिनांक 20.11.92 से 23.11.92 तक राजपैक्स-92

एर्णाकुलम, केरल सर्किल में दिनांक 16.1.93 से 20.1.93 तक केरापैक्स-93

विभाग ने निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय फ़िलैटेलिक प्रदर्शनियों में भी भाग लिया-

ग्रेनाडा में दिनांक 24.4.92 से 3.5.92 तक ग्रेनाडा-92

शिकागो में दिनांक 25.5.92 से 31.5.92 तक एक्सपो-92

कुआलालाम्पुर में दिनांक 1.9.92 से 7.9.92 तक कुआलालाम्पुर-92

एजेंसी सेवाएं

डाकघर बचत बैंक

डाकघर बचत बैंक, वित्त मंत्रालय की ओर से निम्नलिखित योजनाएं चलाता है–

बचत खाता
आवर्ती जमा खाता
सावधि जमा खाता
मासिक आय खाता योजना
लोक भविष्य निधि
इंदिरा विकास पत्र
किसान विकास पत्र
राष्ट्रीय बचत पत्र–आठवां निर्गम
राष्ट्रीय बचत खाता योजना–1992

राष्ट्रीय बचत खाता योजना–1992

राष्ट्रीय बचत योजना, 1987 दिनांक 1.10.92 को बंद कर दी गई और उसी तारीख से एक नई राष्ट्रीय बचत योजना, 1992 आरंभ की गई है। खाते (क) एक वयस्क (ख) दो वयस्कों द्वारा संयुक्त रूप से खोले जा सकते हैं। खाते की देयराशि का भुगतान (i) दोनों में से किसी एक को या उत्तरजीवित को तथा (ग) नाबालिग की ओर से संरक्षक को किया जा सकता है। प्रत्येक जमाकर्ता को प्रतिवर्ष एक अलग खाता खुलवाना होगा। खाता कम से कम 100 रुपए से खोला जाएगा तथा सभी जमा राशियां 100 रुपए के गुणांकों में होंगी। एक माह के दौरान कई बार राशि जमा कराई जा सकती है। 11 प्रतिशत वार्षिक ब्याज एक माह के लिए अनुमत होगा, जैसा कि बचत खाते में होता है। जमाकर्ता जमाराशि उस वर्ष की समाप्ति के चार वर्ष के उपरांत निकलवा सकता है, जिस वर्ष खाता खोला गया था। जिस वर्ष खाता खोला गया था उस वर्ष की समाप्ति के उपरांत चार वर्ष पूरे होने पर खाता बंद करने की अनुमति भी है। प्राप्त ब्याज प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर खाते में जमा कर दिया जाएगा और जमाकर्ता उसे प्रतिवर्ष खाते से निकाल सकता है।

डाकघर बचत बैंक को कम्प्यूटरीकरण के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है। बचत खाता योजना के लिए दिल्ली में 7 प्रधान डाकघरों में, बंबई के दो प्रधान डाकघरों में तथा चंडीगढ़ के एक प्रधान डाकघर में कम्प्यूटर लगाए गए हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के अन्य महत्वपूर्ण प्रधान डाकघरों में भी कम्प्यूटरीकरण का विस्तार करने की योजना है। साथ ही अन्य डाकघर बचत बैंक योजनाओं जैसे आवर्ती जमा योजना तथा मासिक आय योजना में इसके विस्तार द्वारा कम्प्यूटरीकरण के आधार को व्यापक बनाए जाने की भी योजना है। दिल्ली में मौजूदा व्यवस्था का आधुनिकीकरण व उन्नयन किया जाएगा।

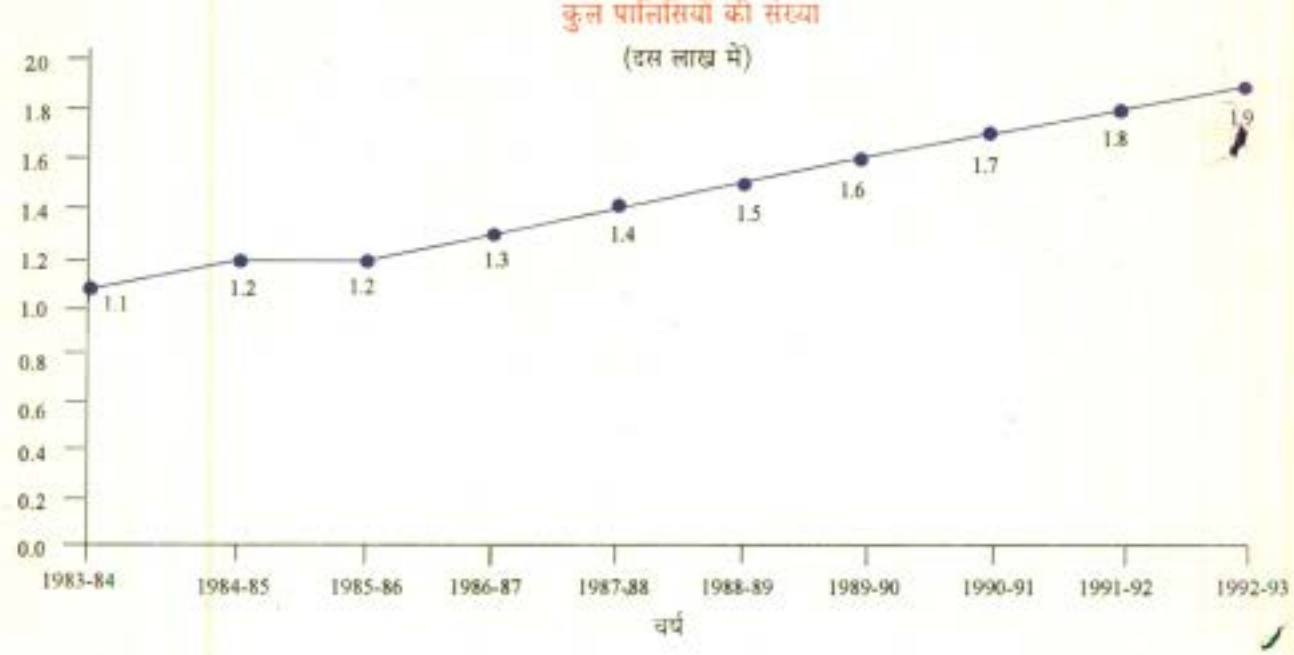

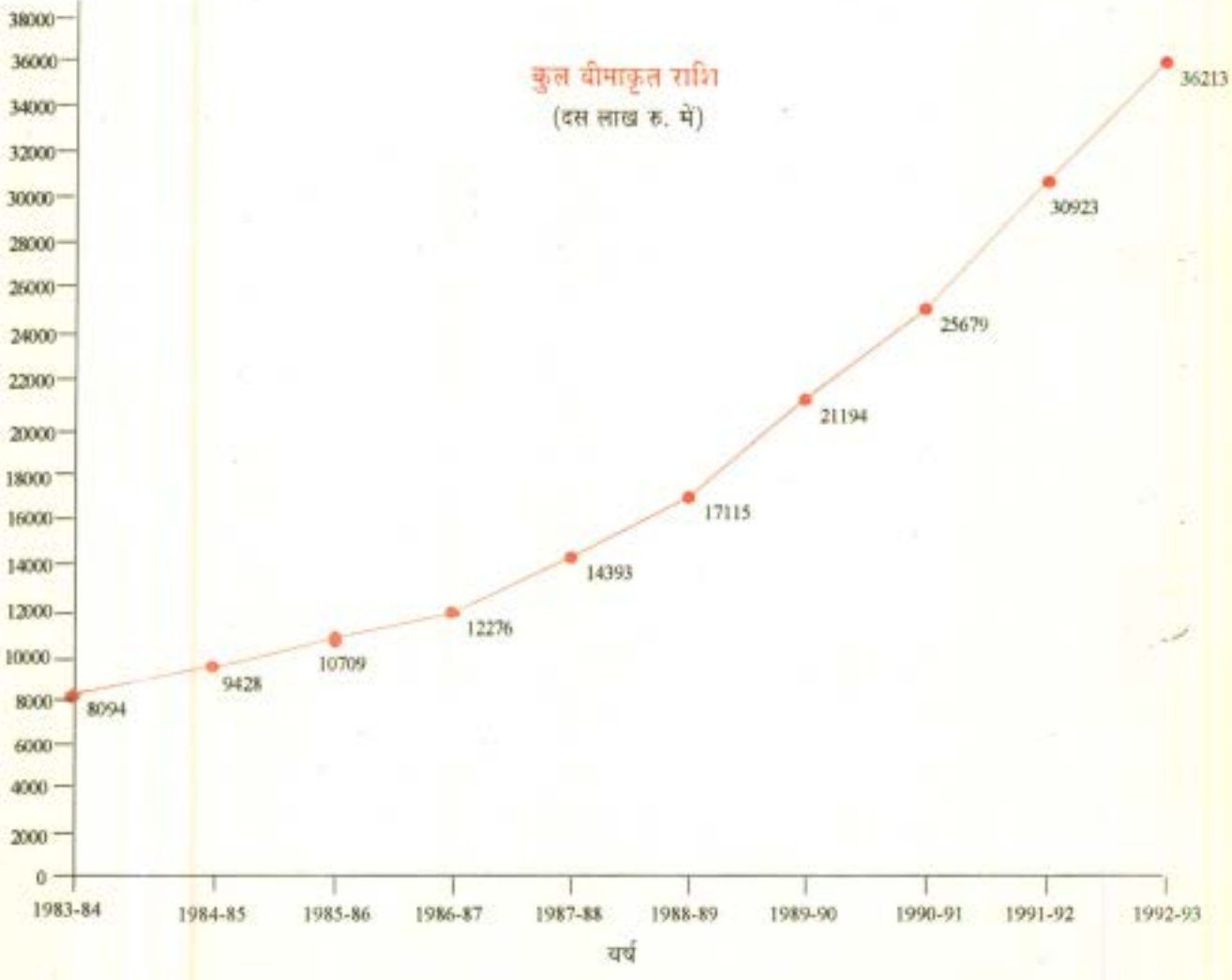

कुल पालिसियों की संख्या
(दस लाख में)
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
1.1
1.2
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1983-84
1984-85
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
वर्ष

कुल बीमाकृत राशि
(दस लाख रु. में)
38000
36000
34000
32000
30000
28000
26000
24000
22000
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
8094
9428
10709
12276
14393
17115
21194
25679
30923
36213
1983-84
1984-85
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
वर्ष

डाक जीवन बीमा

डाक जीवन बीमा द्वारा निम्नलिखित चार प्रकार की पालिसियां प्रस्तुत की जाती हैं, जो इस प्रकार हैं :-आजीवन बीमा, परिवर्तित आजीवन बीमा, बन्दोबस्ती बीमा तथा प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा। गैर-चिकित्सा योजना अधिकतम 20 हजार रुपए तक की बीमाकृत धनराशि हेतु सुलभ है, जबकि चिकित्सा योजना अधिकतम दो लाख रुपए तक की बीमाकृत राशि हेतु सुलभ है।

वर्ष 1992-93 के दौरान 1.51 लाख नई पालिसियां जारी की गईं, इनकी बीमाकृत राशि 576.77 करोड़ रुपए थी तथा वर्ष के अंत तक कुल कारोबार 3621.33 करोड़ रुपए मूल्य की 19,00,580 पालिसियों का था। डाक जीवन बीमा निधि की शेष राशि 31.3.93 की स्थिति के अनुसार 949.4 करोड़ रुपए से बढ़कर कुल 1134.4 करोड़ रुपए हो गई है।

वर्ष 1992-93 के दौरान 47.26 करोड़ रुपए के 54307 दावे निपटाए गए। वर्ष के दौरान 894.83 लाख मूल्य के ऋण जारी किए गए। प्रीमियम आय की तुलना में व्यय का अनुपात 13.71% था।

वर्ष 1993-94 के लिए 668 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

वर्ष के दौरान डाक जीवन बीमा को लोकप्रिय बनाने तथा बिक्री के उपरांत की सेवा को सुधारने और इसे और अधिक ग्राहक-सहयोगी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए :-

दिनांक 1.4.92 से डाक विभाग के अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के लिए सामूहिक बीमा योजना आरंभ की गई। कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों के लिए न्यूनतम तीन वर्ष की नौकरी की शर्त, जैसे स्थानीय निकायों आदि के लिए थी, हटा दी गई।

अब तक डाक जीवन बीमा के कुल 20 सर्किलों में से 12 सर्किलों के कार्य का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है, जिनमें ए पी एस भी सम्मिलित है।

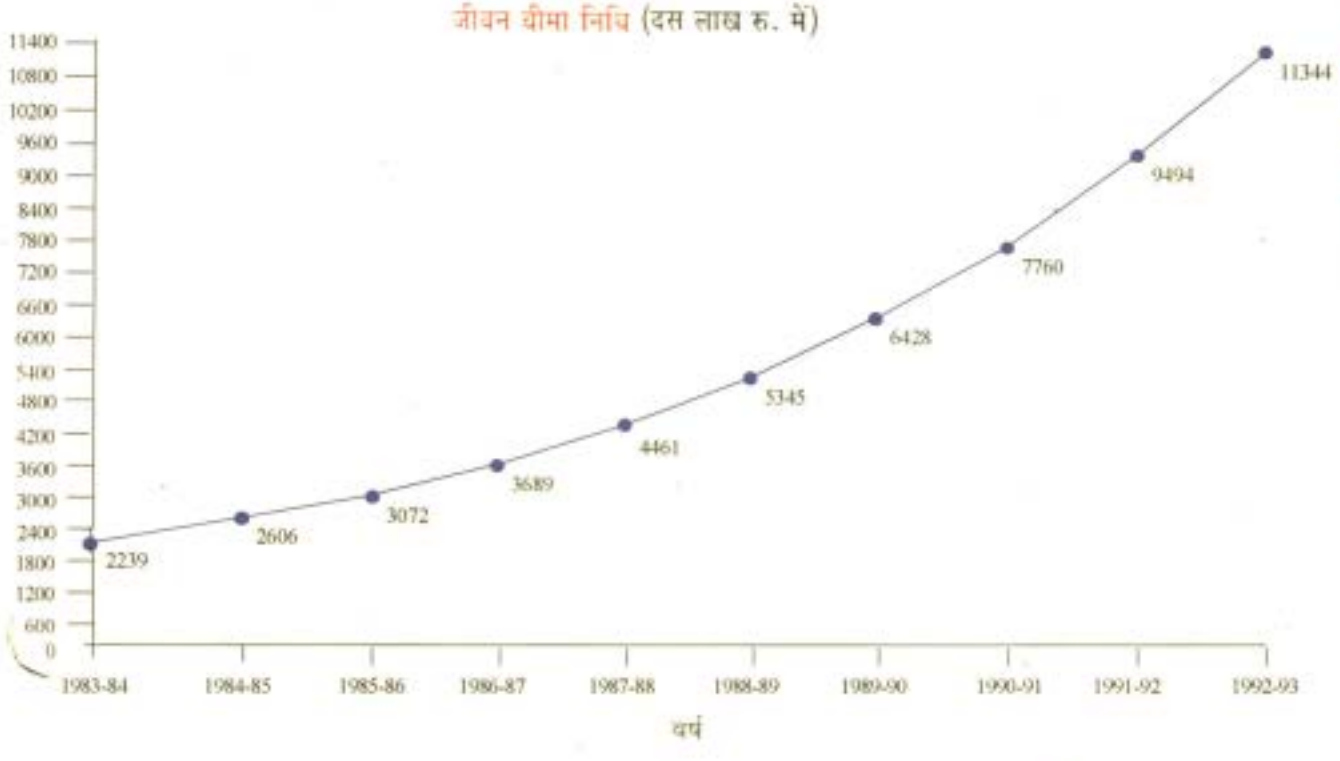

ग्राहक की संतुष्टि

वर्ष 1992-93 के दौरान 717215 जन शिकायतें प्राप्त हुईं और इनकी जांच की गई, जबकि वर्ष 1991-92 में 669950 शिकायतें प्राप्त हुईं। कुल परियात की तुलना में शिकायतों का प्रतिशत 0.00531 है जो गत वर्ष 0.00484 था।

विपणन और वाणिज्यिक प्रचार

विश्व डाक संघ ने 1989 में वाशिंगटन में आयोजित अपनी कांग्रेस में, वाशिंगटन सामान्य कार्रवाई योजना अपनाई। इस योजना ने डाक-प्रशासनों द्वारा कुशल

बाजार–नीतियां अपनाने की अनिवार्यता पर बल दिया। अब तक लगभग सभी डाक–प्रशासन अच्छे जन–संबंधों के सर्वोच्च महत्व का अनुभव कर चुके हैं क्योंकि ये एक प्रमुख जनोपयोगी सेवा प्रदान करते हैं। एक आम बात जो सभी जगह देखी गई, वह यह थी कि सर्वव्यापी डाक सेवाओं के महत्व को समझा नहीं जाता तथा जनसहयोग,जो किसी भी संगठन के लिए, उचित लागत पर ग्राहकों को बेहतर सेवा सुलभ कराने के लिए एक पूर्वापेक्षा है, अच्छे जन–संबंधों और पर्याप्त जनशिक्षा के बिना संभव नहीं है।

ग्राहक की नजरों में विभाग की अच्छी छवि बनाने के लिए तथा स्टाफ का मनोबल बढ़ाने के लिए विपणन प्रयत्न का उद्देश्य सही तथा स्पष्ट पते, मानक माप की डाक लेखन सामग्री के प्रयोग, डाक को समय से भेजने तथा पिन कोड के प्रयोग आदि जैसे अनिवार्य क्षेत्रों में ग्राहकों से सहयोग प्राप्त करना भी है। सफल व समुचित विपणन प्रयत्न के फलस्वरूप लागत कम आती है। यह सेवा में महत्वपूर्ण सुधार लाने के अलावा नेटवर्क में निपटाई जाने वाली डाक की मात्रा को कम करता है।

इसी पृष्ठभूमि में डाक महानिदेशालय की विपणन डिवीजन द्वारा एक व्यापक मिली–जुली छवि के निर्माण की योजना तैयार की गई। इस योजना में प्रेस अभियान, ग्राहकों के लिए संदेशों का प्रचार, ताकि विभाग कम लागत पर बेहतर सेवा प्रदान कर सके, विज्ञापनों के माध्यम से शिक्षा, डाक फोरमों की स्थापना, ग्राहकों की बैठकों तथा गोल मेज सम्मेलनों को आयोजित करना और इसी प्रकार के कार्य शामिल हैं। 18 से 24 जनवरी, 1993 के दौरान पिन कोड सप्ताह का आयोजन, पिन कोड के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम था। पिन कोड का प्रयोग व्यवस्था में डाक–निपटान लागत को घटाने के साथ–साथ स्वचालित डाक संसाधन केन्द्रों के सर्वोत्तम उपयोग की दृष्टि से भी अत्यावश्यक है। डाक सेवा बोर्ड ने विभाग के लिए अधिक राजस्व अर्जन के उद्देश्य से वाणिज्य प्रचार प्रकोष्ठ की गतिविधियों के आधार को व्यापक बनाने के आदेश दिए हैं। डाक लेखन सामग्री पर वाणिज्य विज्ञापन के माध्यम से विभाग ने वर्ष 1991–92 के 1.30 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 1992–93 में 1.62 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया। घरेलू स्पीड पोस्ट परियात वर्ष 1991–92 में 53 लाख था, जो 1992–93 में बढ़कर 73 लाख हो गया। इसी प्रकार 1991–92 में घरेलू स्पीड पोस्ट के लिए 22 करोड़ रुपए का राजस्व था जो 1992–93 में बढ़कर 32 करोड़ रुपए हो गया। गत वर्ष के दौरान शायद ही स्पीड पोस्ट के किसी उत्पाद का परिवर्तन हुआ है। अतः यह कहा जा सकता है कि परियात में वृद्धि का श्रेय, विपणन–प्रयत्नों तथा कुरिअर्स की तुलना में बेहतर कार्य–निष्पादन को है।

पुनः प्रेषण पत्र

वर्ष 1992–93 के दौरान विभाग के 15 पुनः प्रेषण कार्यालयों द्वारा, जो अवितरित डाक का हिसाब रखते हैं, 29.3 मिलियन पत्रों का निपटान किया गया। उनमें से 57 प्रतिशत पत्रों के पतों में सुधार करके उन्हें पाने वाले तक पहुंचाया गया, 28 प्रतिशत पत्रों को उनका पता सुनिश्चित करने के उपरांत प्रेषक को लौटा दिया गया।

डाक परिसर

वर्ष 1992–93 के दौरान विभाग ने भवन–निर्माण तथा संबंधित कार्यों पर 37.20 करोड़ रुपए व्यय किए। इस राशि में से 25.17 करोड़ रुपए विभिन्न डाकघरों तथा प्रशासनिक भवनों के निर्माण पर, 6.41 करोड़ रुपए स्टाफ–क्वार्टरों के निर्माण पर तथा 5.62 करोड़ रुपए भूमि–अधिग्रहण पर खर्च किए गए। 30.88 लाख रुपए डाक प्रशिक्षण केन्द्रों

में भवन-संबंधी गतिविधियों पर खर्च किए गए।

वर्ष 1992-93 के दौरान विभाग ने 98 डाकघर भवनों तथा अन्य कार्यालय-भवनों का निर्माण-कार्य पूरा कर लिया था, 247 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण हुआ, बनकर तैयार हुए 12 स्टाफ क्वार्टर खरीद लिए गए। वर्ष के दौरान 128 कार्यालय-भवनों तथा 375 स्टाफ-क्वार्टरों का निर्माण कार्य आरंभ किया गया।

विभाग ने अपने 32 ऐतिहासिक भवनों को 'विरासत भवनों' की संज्ञा दी है। सर्किलाध्यक्षों को इन भवनों की मरम्मत हेतु विशेष ध्यान देने के निदेश दिए गए हैं। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फार आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज ने मंडी प्रधान डाकघर के साथ-साथ बंबई जीपीओ के लिए भी विभाग को परामर्शदाता नियुक्त किया है, जो 1994 में अपने निर्माण के 200 वर्ष पूरे कर रहे हैं। कलकत्ता जीपीओ के लिए भी, जो अपनी 125वीं जयंती के मध्य में है, विभाग को परामर्शदाता नियुक्त किया गया है। इंटेक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा योजना और वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली, कलकत्ता जीपीओ, लखनऊ जीपीओ तथा अन्य विरासत भवनों की मरम्मत तथा संरक्षण में सम्मिलित हैं। बेंगलूर जीपीओ, हैदराबाद सर्किल कार्यालय आदि जैसे कुछ महत्वपूर्ण भवनों को ''विशेष'' भवन घोषित कर दिया गया है और इनकी बाहरी मरम्मत, अनुरक्षण और देखभाल के लिए विशेष ध्यान दिया गया है।

डाक वित्त

वर्ष 1992–93 का कुल राजस्व 1073.90 करोड़ रुपये था, जो पिछले वर्ष के 947.87 करोड़ रुपए की तुलना में 126.03 करोड़ रुपए (लगभग 13.3%) अधिक था।

वर्ष के लिए प्राक्कलित राजस्व का 108.5% राजस्व वसूल किया गया। यह वृद्धि दरों में संशोधन करने की अपेक्षा बेहतर प्रबंध के कारण हुई।

वर्ष का कुल कार्यकारी व्यय 1165.71 करोड़ रुपए था जो गत वर्ष के 1162.15 करोड़ रुपए के व्यय की तुलना में लगभग 0.3% अधिक था। 1149.36 करोड़ रुपए का व्यय वर्ष 1992–93 के संशोधित प्राक्कलन में दर्शाया गया था। यह वृद्धि मुख्यतः अनुमानित से अधिक सेवानिवृत्तियों के कारण पेंशन संबंधी प्रभारों के अंतर्गत व्यय में होने वाली वृद्धि के कारण हुई। डाक सेवाओं का राजस्व घाटा वर्ष 1991–92 के 214.28 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 1992–93 में 91.81 करोड़ रुपए रह गया। यह 159.36 करोड़ के अनुमानित घाटे की तुलना में भी 67.55 करोड़ रुपए कम था।

राजस्व तथा व्यय 1992–93

(वर्ष 1991–92 की तुलना में)

ब्यौरे	1991–92	1992–93	पिछले वर्ष में परिवर्तित प्रतिशत
राजस्व			
डाक–टिकटों की बिक्री	569.91	609.75	6.99
नकद वसूल किया गया डाक शुल्क	201.31	268.63	33.44
मनीआर्डरों और भारतीय पोस्टल आर्डरों आदि से प्राप्त कमीशन	126.11	135.68	7.58
अन्य प्राप्तियां	50.54	59.84	18.40
कुल	947.87	1073.90	13.29
व्यय			
सामान्य प्रशासन	90.79	103.17	13.63
प्रचालन	1042.76	1132.23	8.58
एजेंसी सेवाएं	54.84	62.87	14.64
अन्य	318.36	350.91	10.22
कुल सकल व्यय	1506.75	1649.18	9.45
कम वसूलियां	344.60	483.47	40.29
निवल व्यय	1162.15	1165.71	0.30

महत्वपूर्ण वर्गों का सकल व्यय निम्नानुसार है :-

	1991–92	1992–93	पिछले वर्ष में परिवर्तित प्रतिशत
वेतन एवं भत्ते, आकस्मिक व्यय और अन्य मदें	1106.22	1246.83	72.71
पेंशन संबंधी प्रभार	182.28	203.64	11.72
लेखा एवं लेखा परीक्षा	33.30	37.65	13.06
डाक-टिकट तथा पोस्टकार्ड आदि	38.81	45.77	17.93
लेखन सामग्री एवं मुद्रणादि	25.74	18.50	(-) 28.13
परिसंपत्तियों का रख-रखाव	7.35	9.14	24.35
मूल्यह्रास	6.00	6.90	15.00
छुट-पुट कार्य	1.68	1.79	6.54
डाक की ढुलाई (रेलवे तथा एयर मेल कैरियर का भुगतान)	105.37	78.96	(-) 25.06
कुल	1506.75	1649.18	9.45

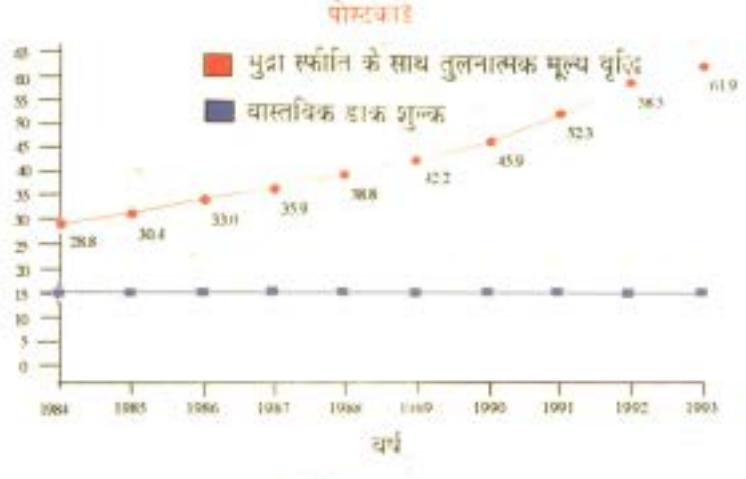

पत्र–कार्ड

राजस्व और व्यय

(दस लाख रु. में)

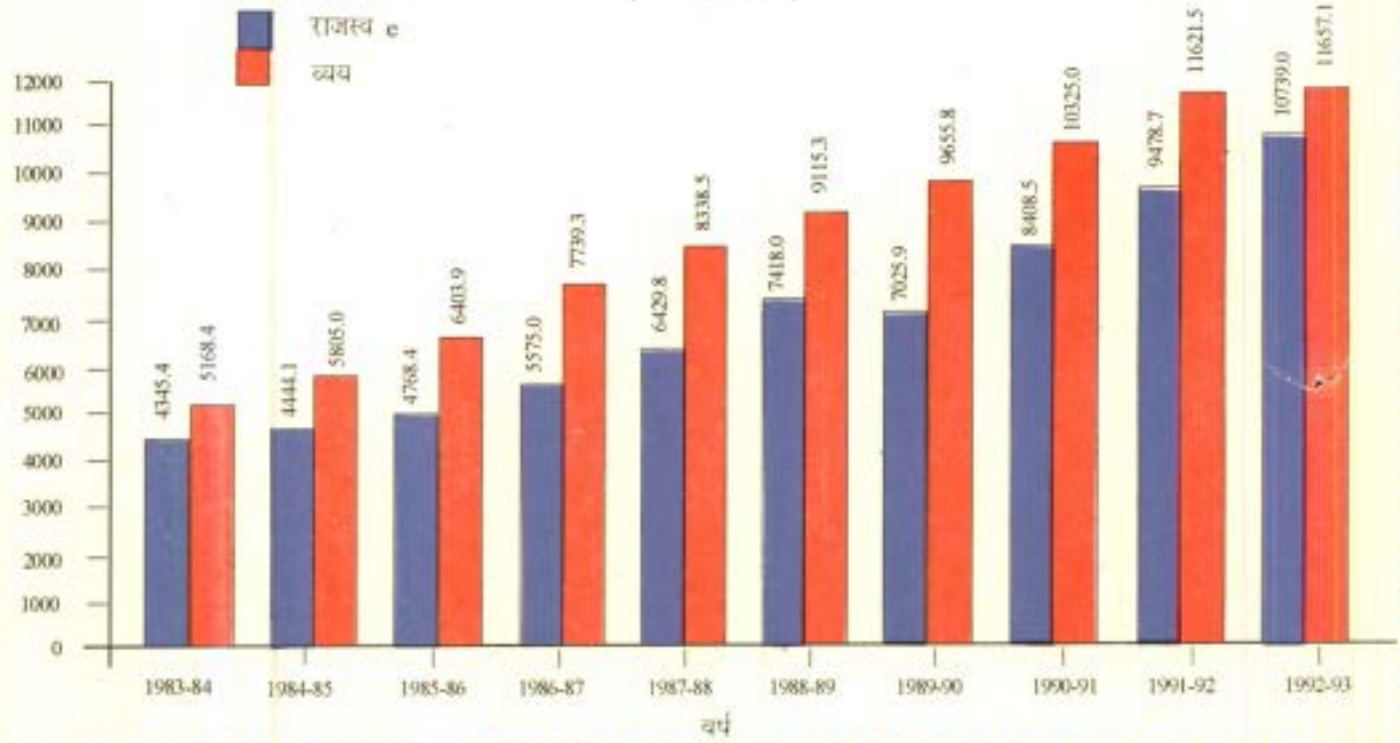

सेवाओं की लागत

वर्ष 1992–93 तथा गत वर्ष में मुख्य सेवाओं की लागत एवं राजस्व, नीचे प्रत्येक सेवा के सामने दर्शाए गए हैं :–

(आंकड़े रुपये में)

सेवा	1991–92 लागत	1991–92 राजस्व	1992–93 लागत	1992–93 राजस्व
पोस्टकार्ड	1.25	0.15	1.54	0.15
मुद्रित कार्ड	1.20	0.60	1.44	0.60
लैटर कार्ड	1.41	0.75	1.57	0.75
पत्र	1.43	1.81	1.78	1.85
पार्सल	18.51	14.31	22.11	17.02
मनीआर्डर	13.16	8.99	14.09	10.97
पंजीकरण	8.76	6.00	10.36	6.00
बीमा	12.66	18.12	13.76	11.01
बुक पोस्ट :				
बुक पैटर्न और सैम्पल पैकेट	1.78	2.42	2.28	1.79
मुद्रित पुस्तकें	2.25	2.26	2.94	1.52
अन्य	2.47	2.11	3.27	1.29

एजेंसी सेवाएं

वर्ष 1992–93 में एजेंसी सेवाओं पर होने वाले कार्यकारी–व्यय की विभाग द्वारा वसूली निम्नानुसार थी :–

(करोड़ रुपयों में)

बचत बैंक एवं बचत पत्र	446.88
डाक जीवन बीमा	27.33
रेलवे पेंशन का भुगतान	1.15
कोयला खनिक/ई पी एफ़ पेंशन	3.57
सीमा शुल्क वसूली	0.91
सेना पेंशन	0.18
अन्य	3.45
कुल	483.47

पूंजीगत व्यय

वर्ष में नियत परिसंपत्ति पर सकल परिव्यय 55.21 करोड़ रुपये था। इसमें से 67.9% व्यय भूमि एवं भवनों पर हुआ और 32.1% उपकरणों और संयंत्रों एवं अन्य पर हुआ। वर्ष के अन्त तक नियत परिसंपत्ति पर पूंजीगत व्यय 513.23 करोड़ रुपये तक बढ़ गया। वर्ष के अंत तक शुद्ध प्रगामी पूंजीगत परिव्यय के लिए सामान्य राजस्व द्वारा 419.52 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई।

मानव संसाधन

मानव शक्ति

इस विभाग के कार्मिक ही भारतीय डाक प्रणाली के मुख्य संसाधन रहे हैं। 31.3.93 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की कुल सं. 5.96 लाख थी। इनमें से 3.06 लाख अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश सेवाएं प्रदान करते हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

डाक विभाग के प्रशिक्षण संस्थानों में निम्नलिखित प्रशिक्षण संस्थान शामिल हैं :-

पोस्टल स्टाफ कालेज, भारत, गाजियाबाद

डाक-तार प्रशिक्षण केन्द्र-सहारनपुर, वडोदरा, मैसूर, दरभंगा और मदुरै में स्थित डाक प्रशिक्षण केन्द्र।

पोस्टल स्टाफ कालेज, भारत, गाजियाबाद एक शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान है,जो डाक विभाग के प्रबंधकीय संवर्गों की प्रशिक्षण-आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस कालेज का मुख्य उद्देश्य भारतीय डाक सेवा, डाक-तार लेखा और वित्त सेवा के अधिकारियों को निम्नलिखित के लिए प्रवेश और सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना है :-

- डाक प्रणाली को अधिक प्रभावशाली और लोगों की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए कर्मचारियों को अपेक्षित जानकारी और दक्षता प्रदान करना और उन्हें व्यवहार कुशल बनाना।
- पांच क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से प्रचालक संवर्गों के व्यावसायिक प्रशिक्षण का संचालन करना।
- डाक प्रणाली के प्रबंध के क्षेत्रों में अनुसंधान का दायित्व लेना।
- एक डाक आंकड़ा बैंक और प्रलेखन केन्द्र का निर्माण करना। इसके अतिरिक्त विश्व डाक संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अनुरोध पर विदेशी प्रशासनों से संबंधित अधिकारियों के लाभ के लिए डाक सेवाओं के विभिन्न पहलुओं पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं।

31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान पोस्टल स्टाफ कालेज, भारत द्वारा 5 प्रवेश प्रशिक्षण और 9 सेवाकालीन पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। कुल मिलाकर इन पाठ्यक्रमों में 209 अधिकारियों ने भाग लिया।

क्षेत्रीय डाक प्रशिक्षण केन्द्रों के मुख्य उद्देश्य हैं :-

- डाक विभाग के समयमान लिपिकीय संवर्गों में भर्ती किए गए कर्मचारियों को प्रवेश प्रशिक्षण देना।
- डाक और छंटाई सहायकों, पर्यवेक्षकों, निरीक्षकों, सहायक अधीक्षक डाकघर और पोस्टमास्टरों इत्यादि को सेवाकालीन पुनश्चर्या प्रशिक्षण देना।
- मध्य स्तर के प्रबंधकीय पदों पर पदोन्नत किए गए अधिकारियों को प्रशिक्षण देना और उन्हें उच्च उत्तरदायित्वों को विश्वासपूर्वक निभाने के योग्य बनाना तथा उनमें डाक और रेल डाक सेवा डिवीजनों के प्रबंध को स्वतंत्र रूप से निभाने के लिए आवश्यक समुचित प्रबंधकीय जानकारी और दक्षता विकसित करना।

इन केन्द्रों में विदेश प्रशासनों से संबंधित अधिकारियों के लिए डाक-तार सेवा में प्रवेश प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाता है। 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान पांच क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में कुल 15,236 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। रॉयल गवर्नमेंट आव भूटान के डाक प्रशासन से संबंधित 15 अधिकारियों को डाक-तार प्रशिक्षण केन्द्र, सहारनपुर में $8\frac{1}{2}$ माह का प्रवेश प्रशिक्षण दिया गया।

पोस्टल स्टाफ कालेज

दिनांक 23-10-92 को स्टाफ क्वार्टर परिसर की नींव रखी गई। कुल मिलाकर 29 क्वार्टर (6 टाइप-I, 8 टाइप-II, 6 टाइप-III, 2 टाइप-IV, 4 टाइप-V, 3 टाइप-VI क्वार्टर) निर्माणाधीन हैं और उनका निर्माण कार्य मई 1994 तक पूरा होने की संभावना है।

पर्यावरण के सुधार के प्रयास स्वरूप वर्ष 1992-93 के दौरान परिसर में 1000 पौधे लगाए गए। परिसर में अब कुल 2000 वृक्ष हो चुके हैं; दूर तक

फैले हुए घास के मैदानों और फूलों की क्यारियों के द्वारा प्राकृतिक दृश्यों की सुरम्यता और अधिक बढ़ गई है। कालेज में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देने के लिए सभी आवश्यक आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं व सामग्री उपलब्ध हैं। कम्प्यूटरीकरण को स्वीकृति दे दी गई है और इसका कार्य प्रगति पर है। छात्रावास में एक साथ 50 अधिकारियों के रहने के लिए सुसज्जित कमरों की व्यवस्था है। परिसर में बिलियर्ड सहित अन्य खेल और मनोरंजन की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

स्टाफ संबंध

विभाग अपने कर्मचारियों और अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की 3 फेडरेशनों और 27 यूनियनों/एसोसिएशनों के साथ स्वस्थ और सार्थक संबंध बनाए हुए है।

अप्रैल 92 से मार्च 93 की अवधि के दौरान डाक विभागीय परिषद् (जे.सी.एम.) की 2 बैठकें आयोजित की गईं। इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान इसकी अपनी समितियों की 28 बैठकें, 4 आवधिक बैठकें, स्थायी समिति की 6 बैठकें, अतिरिक्त विभागीय एजेंटों से संबंधित विभागीय समिति की 3 बैठकें भी आयोजित की गईं। फेडरेशनों/यूनियनों/एसोसिएशनों के साथ बैठकें आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों और अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की विभिन्न मांगों का मैत्रीपूर्ण हल ढूंढना था।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की शिकायतों के 80 मामलों में से 60 मामलों का निपटान कर दिया गया।

आन्तरिक कार्य–अध्ययन

- उप मंडलीय निरीक्षकों से संबंधित मानदंड तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।
- मेल–मोटर सेवा के पर्यवेक्षकीय पदों के लिए मानदंडों से संबंधित अध्ययन पूरा हो गया है।

निम्नलिखित अध्ययनों को वित्त मंत्रालय की निरीक्षण यूनिट (एस.आई.यू.) द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और इनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया चल रही है :–

इन्दिरा विकास पत्रों की बिक्री।

इलेक्ट्रॉनिक एडिंग एंड लिस्टिंग मशीन पर कार्य करने के लिए एल. डी. सी. (एसबीसीओ) की बारी निर्धारित करना।

स्पीड पोस्ट मदों की बुकिंग।

इन्दिरा विकास पत्रों का भुगतान।

मदन किशोर समिति द्वारा प्रधान डाकघरों/मुख्य रिकार्ड कार्यालयों की लेखा शाखाओं के संबंध में निर्धारित किए गए मानदंडों को युक्तिसंगत बनाना।

निम्नलिखित कार्य–अध्ययन पूरे किए गए :

डाक डिवीजन में आई पी ओ/ए एस पी ओ को लिपिकीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए मानदंडों के विकास से संबंधित अध्ययन तथा छंटाई में प्राप्त और प्रेषण के लिए भेजी गई डाक–वस्तुओं का अध्ययन।

उत्कृष्ट कार्यकुशलता को मान्यता

सराहनीय सेवा को विभाग एवं कर्मचारियों द्वारा सदा मान्यता दी जाती है तथा जिन कर्मचारियों की उत्कृष्ट सेवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिए जाने की आवश्यकता होती है, उन्हें मेघदूत पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। वर्ष 1992–93 के लिए निम्नलिखित कर्मचारियों को, विभाग को दिए गए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मान्यता दी गई है एवं उन्हें मेघदूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है :

श्री रघुवीरसिंह, अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर, हरियाणा सर्किल;

श्री एम. जी. रमन्ना, पोस्टमैन, कर्नाटक सर्किल;

श्री आर. के. सक्सेना, डाक सहायक, उत्तर प्रदेश सर्किल;

श्री आर. रवींद्रन पिल्लई, सहायक अधीक्षक, डाकघर, केरल सर्किल; और

श्री ध्यान सिंह, मेलगार्ड, पंजाब सर्किल।

कर्मचारी कल्याण

डाक सेवा कर्मचारी कल्याण बोर्ड, संचार मंत्री की अध्यक्षता में कार्य कर रहा है। इस बोर्ड का उद्देश्य, विभाग के कर्मचारियों की सुविधाओं और कल्याण, खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित व विकसित करना, उनका आयोजन करना तथा उन पर नियंत्रण रखना है। इस संबंध में बोर्ड को सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त होता है। कर्मचारियों के स्वैच्छिक दान तथा खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा धनराशि एकत्र करने की व्यवस्था अधीनस्थ संगठनों द्वारा की जाती है।

कल्याण बोर्ड की धनराशि, खेलकूद, सामुदायिक केन्द्रों, मनोरंजन क्लबों, प्राकृतिक आपदाओं के समय दी जाने वाली सहायता, शिक्षा छात्रवृत्ति, भ्रमण यात्रा एवं विकलांग कर्मचारियों को दिए जाने वाले अनुदान एवं बच्चों, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों, शिशु गृहों एवं स्कूलों जैसी गतिविधियों के लिए प्रयोग में लाई जाती है।

अवकाशगृह

विभाग, अपने कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के लिए 19 स्थानों पर अवकाशगृह चला रहा है।

खेल

अखिल भारतीय डाक खेलकूद बोर्ड ने वर्ष के दौरान टेबल टेनिस (इंदौर), भारोत्तोलन, पावर लिफ्टिंग, श्रेष्ठ फ़िज़ीक (अम्बाला), बैडमिंटन (कटक), एथलेटिक व साइकिलिंग (त्रिवेन्द्रम), कबड्डी (बंबई), कुश्ती (जालंधर) और शतरंज (शिमला) टूर्नामेंट आयोजित किए।

सरकारी काम-काज में हिन्दी का प्रयोग

विभाग अपने मुख्यालय और अधीनस्थ कार्यालयों में भी भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार राजभाषा के रूप में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयत्नशील है। महानिदेशालय, सर्किल मुख्यालयों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है।

राजभाषा अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के क्रियान्वयन और राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम के अनुपालन के लिए कार्यालयों का निरीक्षण किया जाता है और उनकी कमियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

संसदीय राजभाषा समिति ने 25 कार्यालयों का दौरा किया। समिति के सुझावों को क्रियान्वित किया गया।

प्रोत्साहन और सद्भावना के माध्यम से हिन्दी के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने की नीति को ध्यान में रखते हुए, मुख्यालय और अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। ये योजनाएं इस प्रकार हैं :-

1. अखिल भारतीय डाक राजभाषा शील्ड;
2. डाक विभाग मौलिक हिन्दी पुस्तक पुरस्कार योजना;
3. "डाक पत्रिका" में हिन्दी में मूल लेख लिखने के लिए पुरस्कार;
4. डाक विभाग राजभाषा शील्ड;
5. हिन्दी में मूल नोटिंग और ड्राफ्टिंग के लिए प्रोत्साहन;
6. निबंध प्रतियोगिता;
7. हिन्दी वाक् प्रतियोगिता और
8. हिन्दी प्रश्न मंच।

भाग – 2

वार्षिक रिपोर्ट

1993–94

डाक प्रचालन

हिमाचल प्रदेश के बर्फीले क्षेत्रों, जैसे लाहौल, उदयपुर और किलर पंगी, जो कि शीतकाल में अन्य स्थानों से अलग-थलग पड़ जाते हैं, को भविष्य में सभी प्रथम श्रेणी की डाक, विशेष हवाई छंटाई के माध्यम से समय पर प्राप्त होगी। यह सीमा सड़क संगठन व रक्षा मंत्रालय के साथ हुए एक समझौते के परिणामस्वरूप संभव होगा, जिससे इन क्षेत्रों की काफी समय से लंबित समस्या का समाधान हो सकेगा।

स्वचालित डाक छंटाई केन्द्र

29 अप्रैल, 1993 को बंबई में स्वचालित डाक छंटाई केन्द्र चालू किया गया। प्रौद्योगिक रूप से विकसित यह प्रणाली प्रतिदिन 44 लाख डाक मदों का कुशलतापूर्वक निपटान कर रही है, जो समूचे भारत में प्रतिदिन की डाक मात्रा का 9 प्रतिशत है। यह डाक 30 कोडिंग डेस्कों पर लाई जाती है जहाँ बार कोडिंग के पश्चात् इसे दो लैटर सार्टिंग मशीनों में भरा जाता है, जिनमें प्रत्येक में 30,000 पत्र प्रति घंटे की गति से एक साथ 200 गंतव्य स्थानों के लिए डाक छांटने की क्षमता होती है।

काउंटरों का मशीनीकरण

विभाग की आधुनिकीकरण की योजनाओं में काउंटरों द्वारा दी जाने वाली सेवा सदैव ही आकर्षण का केन्द्र होती है। व्यस्त कार्य-समय के दौरान लंबी लाइनों द्वारा उत्पन्न होने वाले दबावों को कम करने के लिए विभाग ने 1993-94 की वार्षिक योजना के अंतर्गत 1,000 पी. सी. पर आधारित बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें उपलब्ध कराने, उन्हें स्थापित करने व चालू करने के आदेश दिए हैं। दिसंबर 1993 तक 350 मशीनें चालू की गईं।

उपग्रह द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर

देश में 75 स्थानों पर उपग्रह के माध्यम से मनीआर्डरों के प्रेषण के लिए विभाग के पास एक योजना है। इस प्रस्ताव में पी. सी. तथा वी. एस. ए. टी. (वेरी स्माल एपेरेटस टर्मिनल्स) को स्थापित किया जाना शामिल है। मार्च 1994 तक देश के पांच स्थानों-दिल्ली, मद्रास, बेंगलूर, लखनऊ और पटना में इसकी व्यापक प्रायोगिक परियोजना को प्रारंभ किया जाना है।

यांत्रिक उपस्करों का प्रयोग

डाक-टिकटों के विरूपण की गुणवत्ता और सुपाठ्यता में सुधार लाने के लिए ऑर्डनेन्स फैक्ट्रीज ऑर्गनाइजेशन को 25,000 हाथ की मोहरों के निर्माण के आदेश दिए गए हैं। आवक और जावक डाक मदों की स्टैम्पिंग के शीघ्र निपटारे के लिए देश के महत्वपूर्ण डाकघरों को 270 डाक-टिकट विरूपण मशीनों की आपूर्ति भी की जा रही है।

डाक नेटवर्क का विस्तार

वार्षिक योजना में 600 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर व 100 विभागीय उप-डाकघर खोले जाने के लक्ष्य की अपेक्षा 31.12.93 तक 519 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर व 16 विभागीय उप-डाकघरों की मंजूरी मिली है। शेष 81 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर व 84 विभागीय उप-डाकघर 31.3.1994 तक मंजूर कर दिए जाएंगे।

फिलैटली

1.4.93 से 31.12.93 तक 32 स्मारक/विशेष डाक-टिकट जारी किए गए। इनमें "पहाड़ी इंजन" तथा "पुष्पद वृक्ष" पर जारी चार-चार डाक-टिकटों के दो सेट भी शामिल हैं जो फिलैटेलिस्टों के बीच काफी लोकप्रिय हुए। स्वामी विवेकानन्द के शिकागो व्याख्यान, खान अब्दुल गफ्फार खान तथा भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्वर्ण जयंती पर जारी विशेष डाक-टिकटों ने देश में खासी लोकप्रियता अर्जित की।

पूरे देश में 50 फिलैटली ब्यूरो तथा 174 फिलैटली काउंटरों के माध्यम से फिलैटली सामग्री के विक्रय का प्रबंध किया जाता है। 1.4.93 से 31.12.93 तक 7 राज्य/सर्किल स्तरीय प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया।

भारतीय फिलैटेलिक कांग्रेस के सहयोग

से विभाग ने 25.12.93 से 29.12.93 तक कलकत्ता में राष्ट्रीय फिलैटली प्रदर्शनी इन्पैक्स–93 आयोजित की। विभाग ने निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया जहां भारतीय डाक–टिकट प्रदर्शित किए गए व बेचे गए :

- सुराबाया, इंडोनेशिया में 29.5.93 से 4.6.93 तक आयोजित इंडोपैक्स–93
- बैंकांक, थाइलैंड में 1.10.93 से 10.10.93 तक आयोजित बैंकांक–93

यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन

यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की कार्यकारिणी परिषद् तथा डाक अध्ययन सलाहकार परिषद् के वार्षिक सत्र क्रमशः 25.4.93 से 5.5.93 तक तथा 10.10.93 से 27.10.93 तक बर्न में आयोजित किए गए। दोनों ही सत्रों में डाक विभाग के सचिव श्री एस. के. पार्थसारथि ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

दिनांक 1.9.93 से 9.9.93 तक कोबे, जापान में आयोजित ए. पी. पी. यू. की कार्यकारिणी परिषद् के वार्षिक सत्र तथा ए. पी. पी. यू. प्रशिक्षण केन्द्र के शासी परिषद् की बैठक में दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत का नेतृत्व किया।

सार्क

सार्क की संचार तकनीकी समिति का अध्यक्ष होने के नाते भारत ने 12.4.93 से 23.4.93 तक "डाक–प्रचालन के मशीनीकरण" पर एक कार्यशाला का आयोजन किया तथा 24 से 25 मई, 1993 तक सार्क की संचार तकनीकी समिति की पहली बैठक की मेजबानी की। सार्क गतिविधियों के अंतर्गत 18 से 23 दिसंबर, 1993 तक बंगलादेश में "ई. एम. एस. की वितरण प्रणाली" तथा 21 से 22 दिसंबर, 1993 तक नेपाल में "डाक–प्रचालन की रक्षा एवं सुरक्षा" पर आयोजित दो पाठ्यक्रमों में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। पोस्टल स्टाफ कालेज, गाजियाबाद में 24 जनवरी से 11 फरवरी, 1994 तक "प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण" पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

द्विपक्षीय सहयोग

अपने भारत दौरे के दौरान उजबेकिस्तान के राष्ट्रपति ने डाक तथा संबद्ध मामलों के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर एक समझौता किया। 5.1.1994 को इस पर संचार राज्य मंत्री तथा उजबेकिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

चीन डाक प्रशासन का एक प्रतिनिधि–मंडल वहां के डाक व दूरसंचार उपमंत्री के साथ भारत आया। 23.11.93 को उन्होंने भारतीय पक्ष से भेंट वार्ता की।

20.9.93 से 24.9.93 तक आकलैंड, न्यूजीलैंड में आयोजित दसवें राष्ट्रमंडलीय डाक प्रशासन सम्मेलन में श्री एस. आर. फारूकी, सदस्य (विकास) ने भारत का प्रतिनिधित्व किया।

सर्किल अध्यक्षों का सम्मेलन, 1993

29 और 30 जुलाई, 1993 को नई दिल्ली में डाक सर्किलों के अध्यक्षों का सम्मेलन आयोजित किया गया। संचार राज्य मंत्री ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। मंत्री महोदय ने डाक के शीघ्र वितरण की महत्ता पर जोर दिया। अपने उद्घाटन भाषण में मंत्री महोदय द्वारा दिए गए विभिन्न सुझावों के अनुसरण में सम्मेलन में महानगरों में डाक के निपटान तथा अन्य मामलों पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

महिला समृद्धि योजना, 1993

ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के उद्देश्य से 1.10.93 से यह नई योजना प्रारंभ की गई। इस योजना में ग्रामीण महिलाओं, जो इसके अंतर्गत धन जमा करेंगी, को अधिकतम 75/– रु. प्रतिवर्ष की शर्त के अधीन 25 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि प्रतिवर्ष दी जाएगी।

डाक जीवन बीमा

इस क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए वे निम्नलिखित हैं :–

1. गैर चिकित्सा योजना की उच्चतम सीमा 20,000/– रु. से बढ़ाकर 1,00,000/– रु. कर दी गई है। महिलायें जो अब तक इसके अंतर्गत नहीं आती थीं, अब इसमें शामिल कर ली गई हैं।
2. प्रीमियम के भुगतान के लिए रियायत की अवधि 21 दिन से बढ़ाकर एक कैलेंडर मास कर दी गई है।

राजभाषा

राजभाषा शाखा ने "डाक प्रशासन शब्दावली एवं मानक मसौदे" नामक पुस्तिका का प्रकाशन किया, जिसे निदेशालय में वितरित किया गया। संचार राज्य मंत्री द्वारा "डाक विभाग राजभाषा शील्ड", जिसमें नगद पुरस्कार भी शामिल हैं, प्रदान की गई। निदेशालय में पहली बार निदेशक स्तर के अधिकारियों के लिए एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। निदेशालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों में 14 से 20 सितंबर, 1993 तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया, जिसके दौरान विभिन्न कार्यक्रम/प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं और पुरस्कार वितरित किए गए। विभाग द्वारा त्रिवेन्द्रम में 19 और 20 जनवरी, 1994 को पहले राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया।

Part - 1
Annual Report
1992-93

OVERVIEW

In the year 1992-93 the Department of Posts carried forward its programme of modernization based on latest technological developments, consistent with resources, both human and financial, available within the Department. The process was steady and strong, resulting in extension of modernization to several wings of the Department. Highlights of the year under review include the successful commissioning of the Automated Mail Processing Centre at Bombay, and increased supply of computerised multi-purpose counter machines at Post Offices. Mention also needs to be made in this connection of the country-wide postal strike which commenced on 7.12.93 and which came to an end on 11.12.93 following the meeting of the Union representatives with Minister of State for Communications. The focus of this overview is on changes in the work and management techniques, Post's financial position and current priorities.

Mail Mechanization

The basic function of the Department has traditionally been the collection, processing, transmission and delivery of mail. Most of these operations are manual. However a beginning was made in the area of modernization and mechanization of mail processing by installing two letter sorting machines with 30 bar coding desks in Bombay which have speeded up sorting of mail emanating from this highly urbanized region. Similar sophisticated mail processing systems are planned for Madras, Delhi, Calcutta and Bangalore.

Counter Mechanization

102 PC based multi-purpose counter machines were supplied to 22 Post Offices in 7 cities. A further order for 750 machines has been placed and is expected shortly.

Postal Equipment

In order to improve the quality of stamps, order for the manufacture of 25,000 hand stamps have been placed with the Ordnance Factories Organization and supply has started. The Department also placed an order for supply of 270 stamp cancelling machines which will be supplied to the larger and more important Post Offices.

Speed Post

Speed Post Service has been further consolidated and commensurate with the objective of the Department, International Speed Post links were established with 13 more countries- Ghana, Hungary, Malaysia, Morocco, Guyana, Uganda, Denmark, Iran, Mexico, Niger, Panama, Papua New Guinea and Zaire.

Speed Post carries with it an assurance of safe and prompt delivery. Having regard to the impressive record of the service in this respect, with effect from 17.8.1992, full refund of Speed Post charges is allowed in case of delayed delivery.

The Speed Post traffic grew by 38% and the revenue by 45%.

Review of The India Post Office Act

The Act which governs the postal system in the country has been under review and revision since 1960. Two legislative efforts were made in 1983 and 1986. The 1986 Bill, though passed by both Houses of Parliament was returned in 1990 for reconsideration by both the Houses. Meanwhile, the need for

further change was recognised. A Committee was therefore constituted in 1992 with the following terms;

to examine the Act in all its aspects with particular regard to, inter alia:-

(i) the developments in communication by mail in the country in recent years and likely trends in the future and the challenges from them to the Post Office;

(ii) the developments in international postal system and the responsibilities that they impose on the Post Office;

(iii) the difficulties at present felt by the Post Office in practice on account of the limitations of the Act; and

(iv) the legal liability that the Post Office should accept for its services, in the context of the growing consumer protection trends, and consistent with the magnitude of its services, the conditions under which they are rendered and at relatively low postage and fee;

and suggest modification to the Act and furnish an appropriate draft legislation.

The Committee's report was examined by the Postal Services Board and all recommendations made were processed. New draft legislation, based on the report is under finalization.

Bulk Mail Centre and Presort Rebate

The new thrust in operational policy is evident in the decision to establish Bulk Mail Centres in major cities for handling registered and unregistered mail posted in bulk. This special unit is primarily meant to facilitate postal transactions of share and debenture certificates, refund orders and dividend certificates, refund orders and dividend warrants and other letter mail from the corporate sector but open to others also. Letters numbering 10,000 or more when unregistered and 250 or more when registered, posted across the counter by a single mailer will be considered bulk mail. Bulk Mail Centres will accept only the presorted mail. Pre Sorting in accordance with the Department's requirement will entitle the mailer for the rebate of 2% of the postage in addition to the existing rebate for the user of a franking machine. For registered articles, the rebate extends to the registration fee also.

Performance Indicator

A significant management exercise that fructified in 1992-93 was the introduction of Performance Indicators to evaluate the individual performance of each Circle progressively and in relation to other Circles. The Scheme entails management evaluation of a Postal Circle with all the key aspects such as development, operations, finance and personnel welfare factored in. Performance depicted against each indicator gives the Head of the Circle vital management input for planning the various management steps in specific directions.

Expansion of Postal Network

In the context of the 8th Plan objectives, special emphasis is proposed to be placed on hilly, desert, tribal areas, for the expansion of the Postal Network. The number of EDBOs targeted to be opened in the tribal, hilly and backward areas during the Plan was 1500. The target for the year 1992-93 has already been exceeded. For 1993-94 the target of 600 EDBOs and 100 DSOs has been set. Of these 230 EDBOs and 20 DSOs are to be opened in the tribal belts. By August 1993, sanction orders for

opening 358 EDBOs have been issued.

Marketing

Significant changes can be seen in the Marketing Division. The Indian Postal Administration fully appreciates the importance of good public relations, public education and information dissemination. Marketing efforts are cost effective only when there is public awareness and customer attitude is positive.

Against this background, the Marketing Division formulated a comprehensive Corporate Image Plan and the customer friendly campaigns presented through newspapers and magazines have generally received favourable public response. Various market surveys by independent agencies have also been commissioned so as to design services oriented to customer needs.

International Relations

The Indian Postal Administration further strengthened its international bonds by hosting the annual meeting of the Executive Council of the Asian Pacific Postal Union and the 22nd meeting of the Asian Pacific Postal Training Centre Governing Board. The Hon'ble Vice President of India, Shri K.R. Narayanan inaugurated the deliberations of the Executive Council of the Asian Pacific Postal Union on 17th September, 1992.

The annual session of the Consultative Council for Postal Studies (CCPS) of the Universal Postal Union was held at Berne from October 12 to October 23, 1992. The Indian delegation was led by the then Secretary, Department of Posts, Shri L.D. Bonnell.

India held a meeting of the Indo-French working group on the Posts. The French delegation was led by the Minister for Post & Telecommunication.

Exporters in the Varanasi area now have a new facility. An export extension postal window has been opened at the Babatpur Cargo Complex.

Two Indian Postal experts conducted studies for SAARC on mail transmission norms and concessional mail tariff.

Philately

In order to cater to the interests of the growing number of philatelists in the country, the Department operates 50 Philatelic Bureaux and 174 Philatelic Counters in major Post Offices. Karnataka, Rajasthan and Kerala Circles held state level philatelic exhibitions. The Department of Post participated in three International Philatelic exhibitions at Granada, Chicago and Kuala Lumpur.

Corporate Identity

A notable development in the public relations of the Post Office was the adoption of a corporate logo. Depicting two pairs of wings, in Post Office red, with the legend "Bharatiya Dak" and "India Post", the logo was formally introduced on October 9, 1993.

Finance

The total revenue during the year under review (1992-93) was Rs. 1073.90 crores (registering an increase of Rs. 126.03 crores) against the receipts of Rs. 947.87 crores in 1991-92. The net working expenses of the year were Rs. 1165.71 crores as compared to the preceding year's expenditure of Rs. 1162.15 crores. The estimated expenditure projected in R.E. 1992-93 was Rs. 1149.36 crores.

The aggregate Expenditure-Revenue gap shrunk to Rs. 91.81 crores from the previous year's gap of Rs. 214.28 crores. This reduction of more than Rs. 120 crores was achieved through better collection of revenue, stopping of leakages, improved financial management, and strict economy.

ORGANISATION

The Department of Posts was created in January, 1985 after the bifurcation of the erstwhile Posts and Telegraphs Department. It forms part of the Ministry of Communications. During the year under review, the Department continued to function under Shri Sukh Ram, Minister of State for Communications (independent charge).

Headquarters

The management of the Department vests in the Postal Services Board. The Chairman of the Board is also the Secretary, Department of Posts and the Director General, Posts. There are three members of the Board, holding the portfolios of Operations, Development and Personnel. In addition, there is a Financial Adviser.

The Board is assisted by a Secretary, who is also Sr. Dy. Director General (Inspection and Efficiency Bureau). The Board directs and supervises the management of the Postal Services in the country with the assistance of eighteen Deputy Directors General in the Directorate General of Posts.

Circles

The Department's operational responsibilities are borne by nineteen Postal Circles. A Circle comprises one or more State/Union Territories and is headed by a Chief Postmaster General and is generally divided into Regions comprising a group of field units called Divisions. Each Region has a Postmaster General and provides high level management support to the Chief Postmaster General in the field.

In addition to the Circles, there are Regional Mail Planning Units at Bombay, Calcutta, Delhi and Madras under Controllers of the rank of Postmaster General. The controllers bring exclusive professionalism to the planning and control of mail operations. There are also other functional Divisions and Units like Mails Division, Stores Depot, Stamps Depot and Mail Motor Service in a Circle.

Indian Post Offices are categorised as Head, Sub and Branch Post Offices. Branch Post Offices are usually Extra-Departmental Post Offices located in rural areas. Most of the Sub-Post Offices are departmental, and are located in both rural and urban areas. Head Post Offices are graded into five categories according to their workload and staff strength, the biggest being the General Post Offices of Bombay and Calcutta, followed by the GPOs at Madras, Delhi, Ahmedabad, Bangalore, Kanpur, Lucknow and other major cities of the country.

The Army Postal Service is headed by a Major General. He is designated as Additional Director General, APS, and is also described as Chief Postmaster General, APS Circle. Most of the officers and other ranks, including the Major General, are drawn from the civil postal service.

Positions

On 31st March, 1993, the Postal Services Board consisted of Shri S.K. Parthasarathy, Secretary (Posts), Director General, Posts and Chairman, Postal Services Board, Shri M.S. Raghavan, Member (Personnel), Shri T.E. Raman, Member (Operations) and Shri. S.R. Faruqi, Member (Development). Shri G.S. Rajamani, as Joint Secretary and Financial Adviser, Department of Posts, is a

permanent invitee to the Board. Shri B. Parabrahmam was Sr. DDG (I&EB) and Secretary of the Postal Services Board. Currently, Shri S.P. Rai is Member (Personnel) in the place of Shri M.S. Raghavan who retired on September 30, 1993.

International Postal Relations

The Department of Posts hosted the Annual Meeting of the Executive Council of the Asian Pacific Postal Union (APPU) and the 22nd Meeting of the Asian Pacific Postal Training Centre Governing Board at New Delhi from 15th to 21st September, 1992. The meetings were attended by delegates from twenty member countries including India and observers from the Universal Postal Union (UPU) and four other Postal Administrations. The meeting of the APPU Executive Council was inaugurated on September 17, 1992, by Shri K.R. Narayanan, the Hon'ble Vice-President of India. Deliberations were mostly devoted to ways and means of improving the quality of the Postal Services in the Asian-Pacific region. Customers' satisfaction, market oriented approach and training were the areas focussed on during the meeting. India chaired the meeting of the Standing Committee of Technical Cooperation and Assistance of the APPU.

The Annual Session of the Consultative Council for Postal Studies (CCPS) of the Universal Postal Union was held at Berne, Switzerland, from October 12 to 23, 1992. A delegation comprising Shri L.D. Bonnell, Secretary, Department of Posts, Shri S.K. Parthasarathy Member (Personnel) and Shri R.U.S. Prasad, Deputy Director General (International Relations) attended this meeting. Four symposia - on "Human Resources", "Research and Development", "EMS" and "Postal Market" - formed an integral part of this CCPS Session.

A delegation from the French Postal Administration visited India along with the French Minister for Post and Telecommunications. A meeting of the Indo-French Working Group on the Post was held on 24.11.92. A Protocol on cooperation between the two countries in the Postal and Telecom spheres was signed by the Minister of Communications and the French Minister. The areas identified by the Protocol for cooperation in the postal sphere were modernisation of postal services, speed post, training and international mails. It was also decided that it would be mutually advantageous to reinforce cooperation between the two countries in the postal sphere through a fresh Memorandum of Understanding.

The International EMS Network has been extended to thirteen more countries with effect from 1.12.92. As a result, India now has EMS links with 61 countries. An export extension window at Babatpur Cargo Complex Sub-Post Office, at Varanasi, has been opened to facilitate booking of export articles emanating from Varanasi Region.

POSTAL OPERATIONS

Introduction

Postal Operations are often perceived as a single function of delivering letters from one end to the other. As a matter of fact, it is a chain of multifarious interrelated functions such as collection, sorting, transmission, resorting at destination and delivery. In addition, there are ancillary or independent functions like Registration, Money Order, Speed Post, Sale of Stamps and Postal Orders etc. The success of this multiplicity of operations is often dependent on the efficiency of other agencies in the transportation sector such as Airlines, Railways, Roadways and Shipping. The Department of Posts also performs functions on behalf of other Ministries or Departments. Prominent among them are Savings Bank and Postal Life Insurance; these are known as agency functions.

Expansion of Postal Network

In terms of the number of Post Offices, India ranks foremost among the postal systems of the world. This is attributable as much to the vastness of the country and its massive population as to the conscious effort of the Government since Independence to develop the Postal Network as a means of social integration and as an instrument of economic development and rural regeneration. Apart from serving the basic purpose of extending postal communication, the expansion of postal services has also significantly contributed to the achievement of socio-economic goals of the Government such as development, spread of literacy, employment, promotion of small savings and the establishment of industries in backward areas.

Number of Post Offices

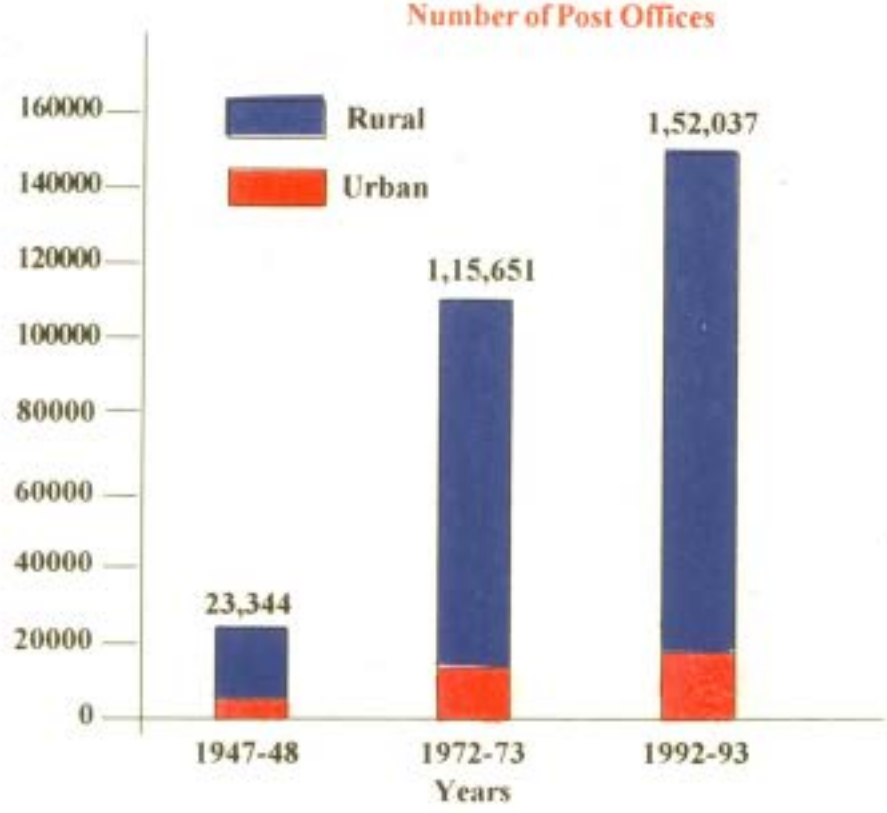

By the end of the Seventh Plan, the National Postal Network encompassed 1,47,236 Post Offices of which 16,249 Post Offices were in the urban sector and 1,30,987 in the rural areas. As on 31.3.93, there were 1,52,037 Post Offices in the country of which 16,283 were in the urban area and 1,35,754 in the rural area. As per 1991 census, a post office covered an average area of 21.6 sq. kms. and an average population of 5553.

The Planning Commission has approved a target of opening 500 Departmental Sub-Post Offices (DSOs) and 3000 Extra-Departmental Branch Post Offices

Postal Traffic since 1983-84
(Adjusted to Revenue)

(In Millions)

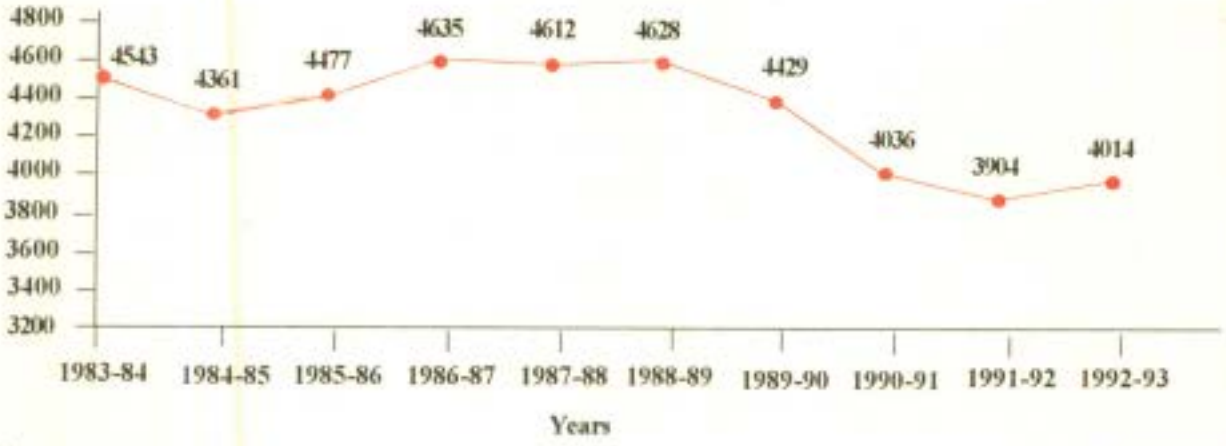

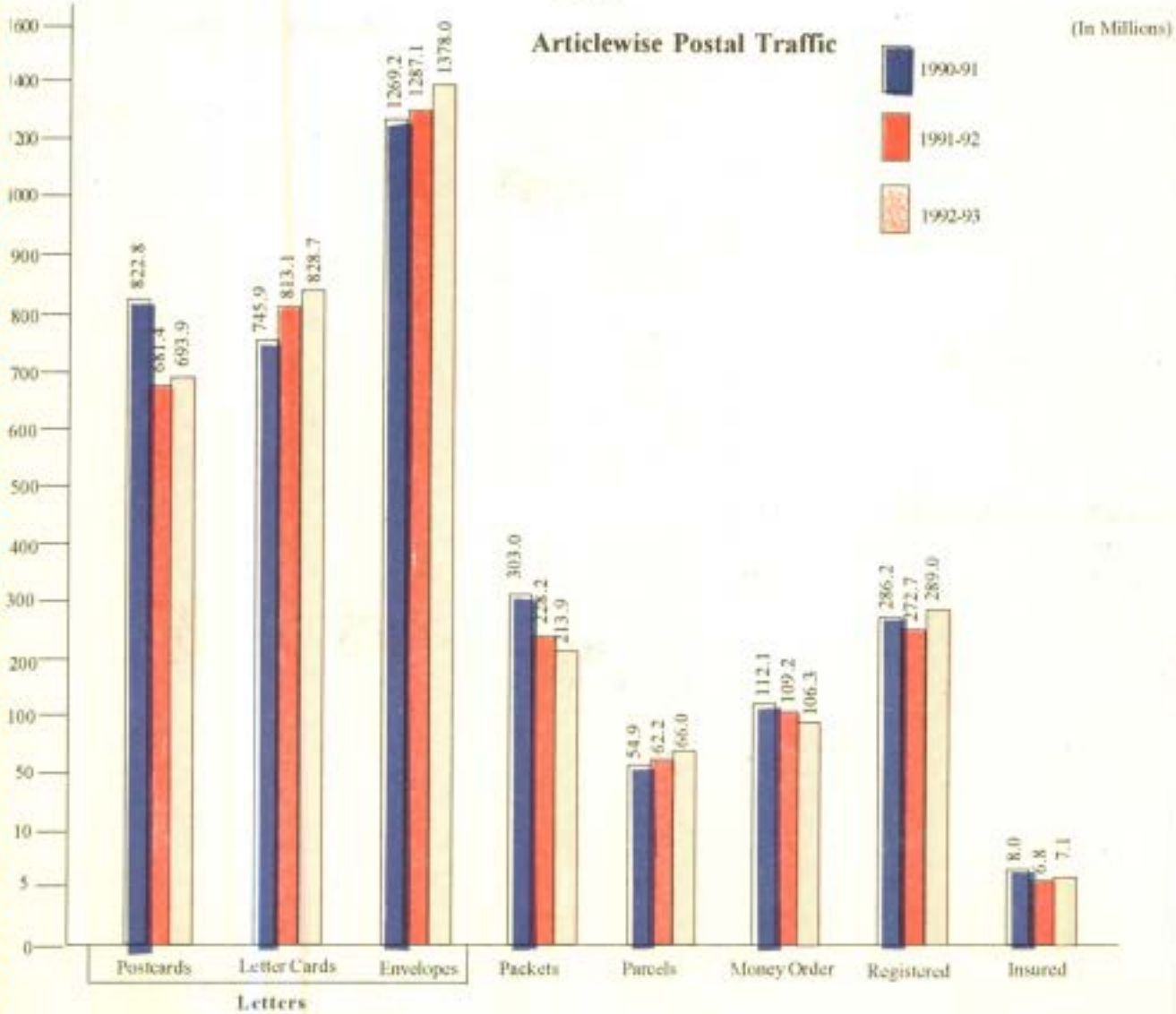

(EDBOs) during the Eighth Five Year Plan (1992-97). In the context of the Eighth Plan, special emphasis is proposed to be given to hilly, desert and tribal areas for the expansion of the postal network. 1500 EDBOs are proposed to be opened under the Tribal Sub Plan during the period.

During the year 1992-93, a total of 635 EDBOs; and 116 DSOs were sanctioned against the target of 600 and 100 respectively.

Mail Volume

Domestic unregistered postal traffic handled during the year 1992-93 totalled 3255 million pieces of mail consisting of 2835 million letters, 378 million packets and 42 million parcels. Domestic registered mail numbered 314 million pieces. During this period, the Department of Posts transmitted 105.3 million Money Orders with their value aggregating Rs. 29124 million.

Services

The Post renders

Mail Services,
namely
Letters,
consisting of:
envelopes,
letter cards,
postcards,
Book Packet

Newspaper Packet

Parcel

classified as:
Ordinary Mail
Posting Certified-
Ordinary Mail

Registration
Value-payable
Insurance
Speed post

Money Transfer Services,
namely
Money Order
Postal Order

Other Services,
namely
Saving Bank
Postal Life Insurance
Telegraph
Telephone Public Call Offices
Telephone Revenue Collection
Passport Application Forms
Central Recruitment Fee Stamps

Speed Post

With effect from Ist December, 1992, International Speed Post links were established with thirteen additional countries, namely, Ghana, Hungary, Malaysia, Morocco, Guyana, Uganda, Denmark, Iran, Mexico, Niger, Panama, Papua New Guinea and Zaire.

A new Speed Post Centre with national network connections

Speed Post Traffic

(In Thousands)

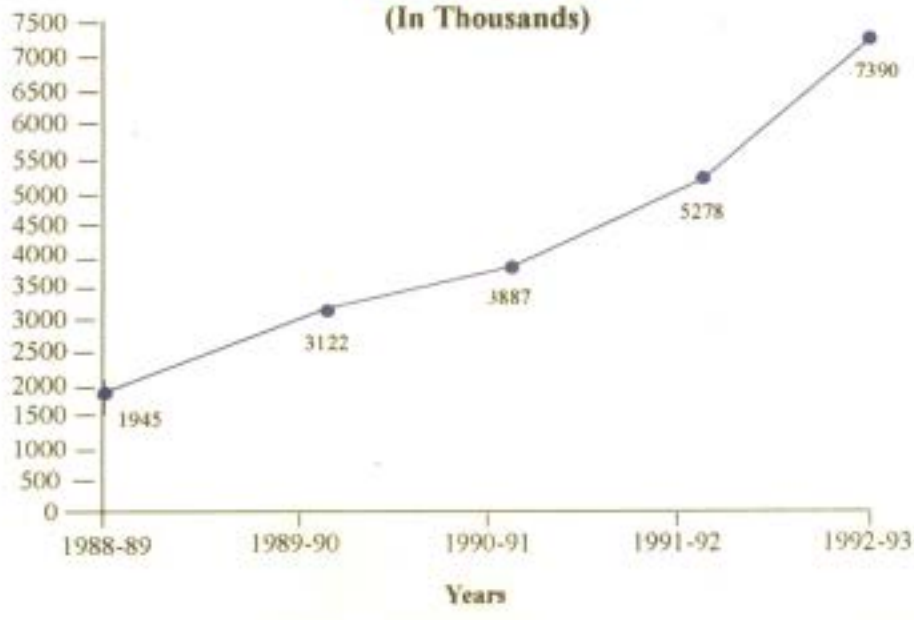

was opened at Howrah on 1.6.1992, raising the total number of national centres to 62 (with six extension counters). Under point to point speed post service, the pairs of stations rose to 737 against the earlier figure of 349. The growth of Speed Post service was 38 per cent in terms of traffic and 45 percent in terms of revenue.

Full Refund of Speed Post charges in case of delayed delivery was introduced from 17.8.92.

Mail Operations

While the Department is modernising mail transmission systems in metropolitan cities, it stands equally committed to improving mail network in the far flung areas of the country. In the recent past, the Department has entered into an agreement with Defence Ministry for transmission of mail from Port Blair to Car Nicobar and back through IAF flights. This has expedited mail movement to and from the remote islands of the archipelago. The various mail monitoring practices have been improved in order to ensure identification of bottlenecks and their removal.

Technology Induction

The advent of modern technology, especially the improvements effected by computers in information technology and electronic data processing, is a global phenomenon and is seen as the need of the hour all over the world. The thrust areas identified for the modernisation of postal services are counter mechanisation, mail mechanisation, electronic money transfer via satellite, introduction of mechanical equipment and aids, and computerisation of Saving Bank, PLI and selected accounting operations.

Mail Motor Service

During 1992-93, Departmental Mail Motor Units functioned at 90 stations. A hundred and twenty four new vehicles were introduced in replacement of old ones for efficient transmission of mails. The total fleet strength was 1103 vehicles which covered a total distance of 1.76 crore kilometers.

Delivery on Holidays

In the past, the Post Office used to deliver fully paid unregistered mail on all post office holidays. This was reduced to three National Holidays in 1974. In 1982, mail delivery on holidays was totally discontinued as a measure of economy. However, based on the experience of intervening years, it was found necessary to give some relaxation to the measure because, when holidays ran consecutively, the mail was not delivered to the public for two or more days causing inconvenience to the public as well as to the postal staff in so far as they had to deal with a much larger volume of mail on the next working day. In September 1992, orders were issued introducing one delivery of fully paid, unregistered mail on post office holidays, except National Holidays and Sundays. This now ensures that there are never more than two days at a stretch without delivery of mail.

Corporate Post Offices in Delhi

Two Bulk mail Centres were opened in Delhi in 1992 to process presorted mail posted in bulk. These have been followed with centres at Bombay and elsewhere.

Passport Application Forms

Sale of Passport Application forms was introduced at selected post offices on 1.11.1992. All Head Post Offices and about 1000 selected Sub Post Offices now sell these forms.

CRF Stamps

Sale of Central Recruitment Fee stamps was extended to all Departmental Post Offices from 1.1.93.

Philately

Thirty seven special/ commemorative stamps were issued from 1.4.92 to 31.3.93. These included three sets of four stamps each and two sets of two stamps each. Inland letters in pink and light grey were introduced. These are in addition to the bluish green ones already available. Another innovation was light sea green and light blue post cards.

Fifty Philatelic Bureaux and 174 Philatelic Counters were functioning in the country as on 31.3.93. The following State level philatelic exhibitions were held during the year:-

Karnapex-92 at Mysore, Karnataka Circle, from 11.9.92 to 13.9.92.

Rajpex-92 at Jaipur, Rajasthan Circle, from 20.11.92 to 23.11.92.

Kerapex-93 at Ernakulam, Kerala

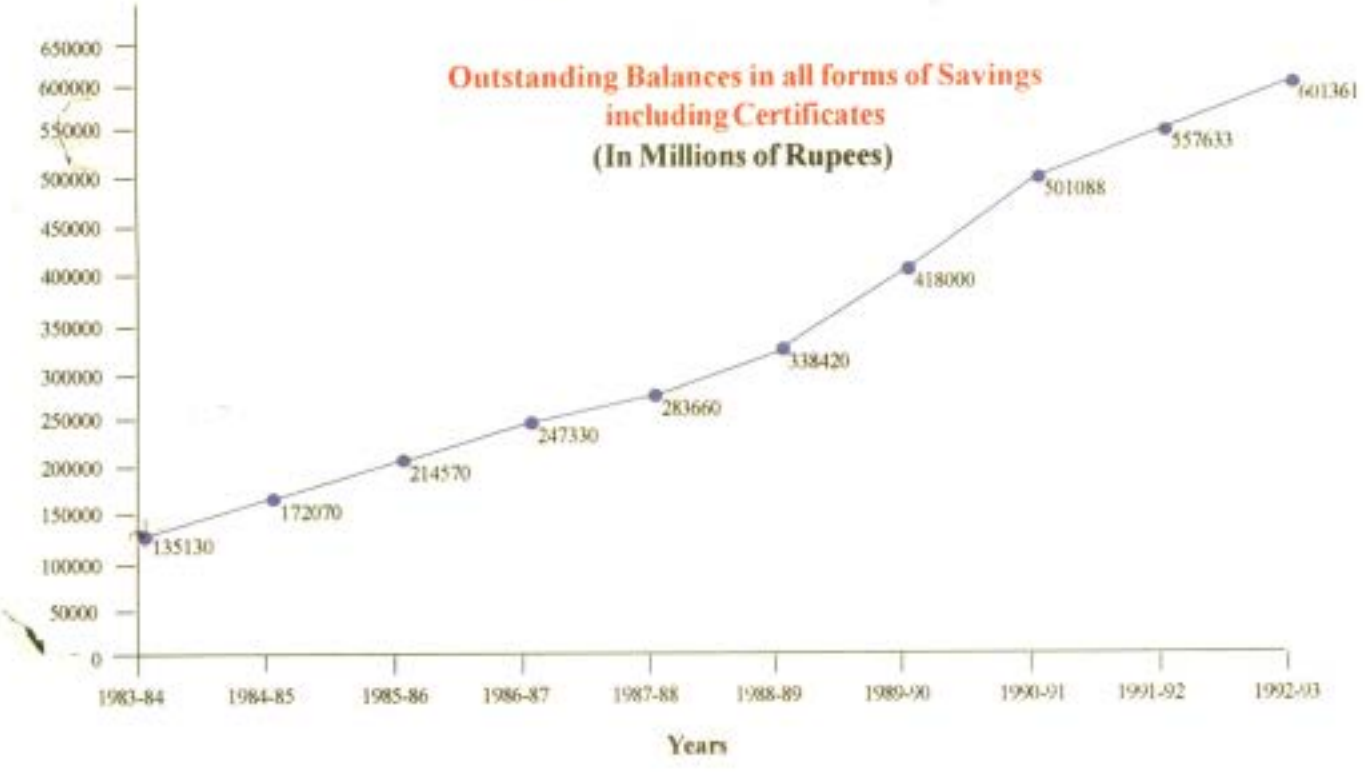

Circle, from 16.1.93 to 20.1.93.

The Department also participated in the following International Philatelic Exhibitions:-

Granada-92 in Granada, from 24.4.92 to 3.5.92.

Expo-92 in Chicago, from 22.5.92 to 31.5.92.

Kuala Lumpur-92 in Kuala Lumpur, from 1.9.92 to 7.9.92.

Agency Services

Post Office Savings Bank

The Dept. of Posts operates the following schemes on behalf of the Ministry of Finance :-

Savings Accounts
Recurring Deposit Accounts
Time Deposit Accounts
Monthly Income Accounts Scheme
Public Provident Fund
Indira Vikas Patras
Kisan Vikas Patras
National Savings Certificates - 8th Issue
National Savings Accounts Scheme 1992

National Savings Accounts Scheme - 1992

N.S. Scheme, 1987 was discontinued on 1.10.92 and a new National Savings Scheme 1992 has been introduced with effect from the same date. Accounts can be opened by (a) single adult (b) two adults jointly, the amount due on the account being payable to (i) both jointly or survivor; or (ii) either or survivor and (c) a guardian on behalf of a minor. A separate account has to be opened by every depositor for each year. The account should be opened with a minimum of Rs. 100/- and all deposits shall be in multiple of 100/- rupees. Any number of deposits can be made during a month. Interest @ 11 per cent shall be allowed for a calendar month as in Savings Account. The depositor can withdraw the amount after expiry of four years from the end of the year in which the account is opened. Closure of the account is also permitted after expiry of four years from the end of the year in which account was opened. The interest accrued will be deemed to have been credited in the account at the end of each year and can be withdrawn by the depositor every year.

The Post Office Savings Bank has been identified as an important area for computerisation. Computers have been commissioned for Savings Account Scheme in seven HPOs in Delhi, two HPOs in Bombay and

Total Number of Policies

(In Millions)

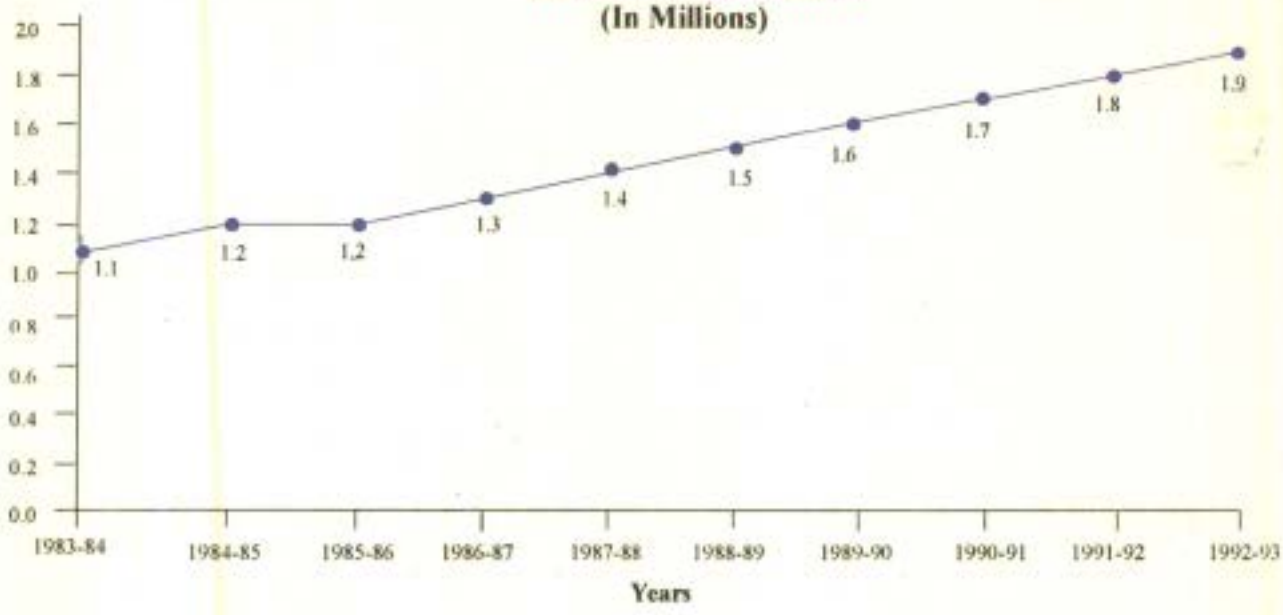

Total Sum Assured

(In Millions of Rupees)

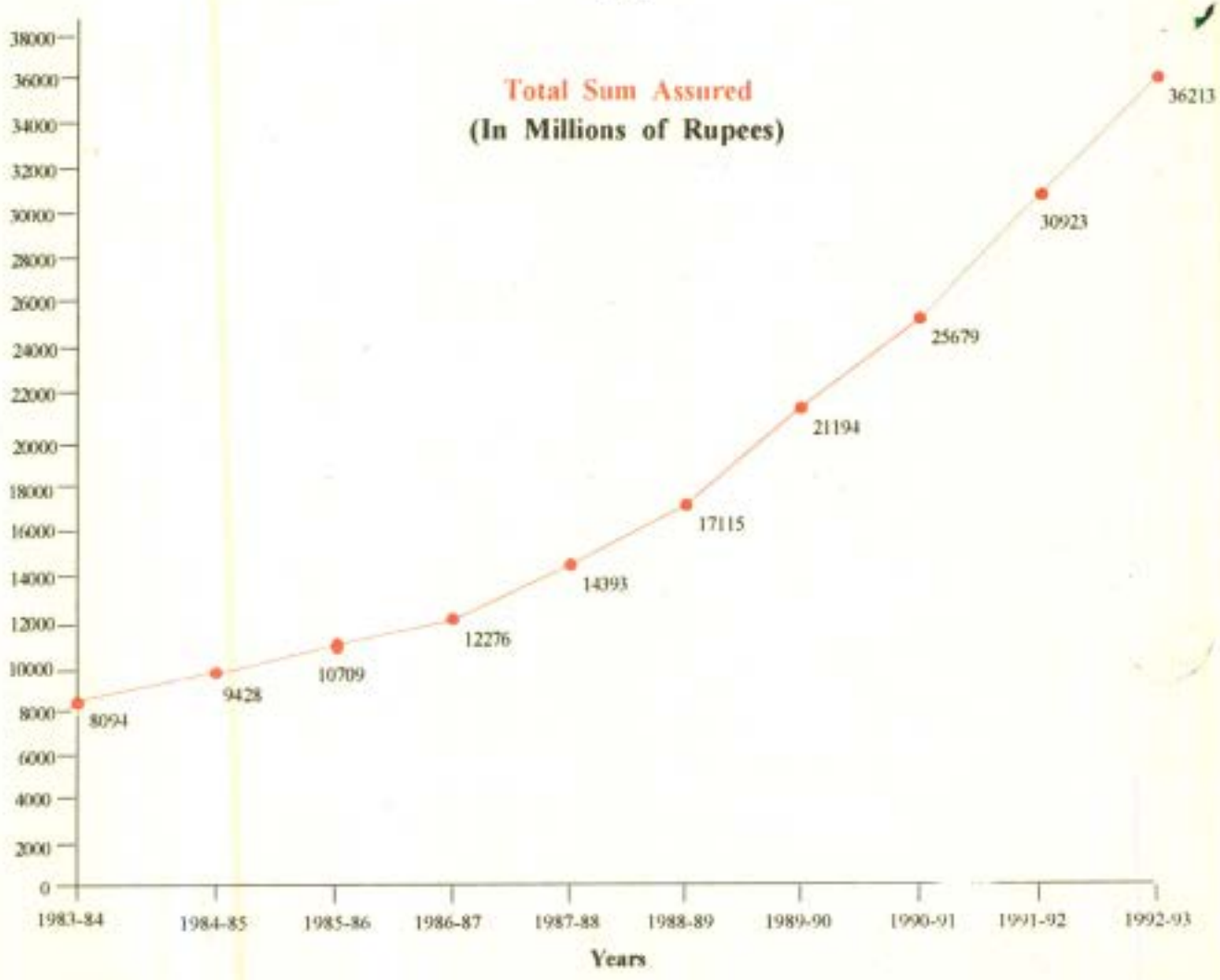

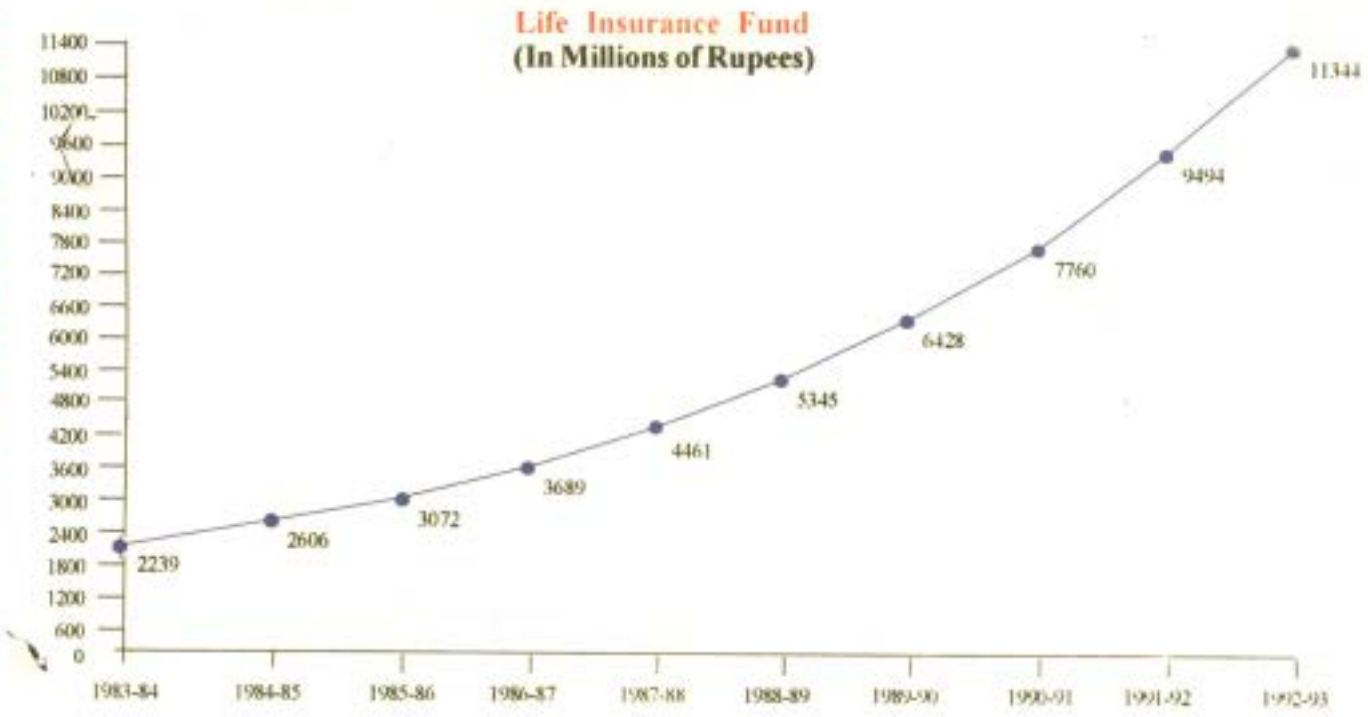

one HPO at Chandigarh. During the eighth Five Year Plan, it is planned to extend computerisation to other important HPOs in the country and to broadbase the computerisation by its extension to other POSB schemes, such as RD and MIS. The system already in place in Delhi will be modernised and upgraded.

Postal Life Insurance

Postal Life Insurance offers four types of policies, namely, Whole Life, Convertible Whole Life, Endowment Assurance and Anticipated Endowment Assurance. The non-medical scheme is available up to a maximum sum assured of Rs. 20,000/- while medical scheme is available up to a maximum sum assured of Rs. 2.00 lakhs.

During the year 1992-93, 1.51 lakh new policies were issued with sum assured of Rs. 576.77 crores and the total business at the end of the year stood at 19,00,580 policies with an aggregate sum assured of Rs. 3621.33 crores. The total of the Postal Life Insurance Fund Balance has risen from Rs. 949.4 crores to Rs. 1134.4 crores as on 31.3.93.

As many as 54307 claims of the value of Rs. 47.26 crores were settled during 1992-93. Loans of the value of Rs. 894.83 lakhs were issued during the year. The expense ratio to premium income worked out to 13.71 per-cent.

For the year 1993-94, a target of Rs. 668 crores has been fixed.

The following steps were taken during the year to popularise PLI, improve the after sales service and make it more customer friendly.

Introduction of Group Insurance Scheme of Extra-Departmental Agents of the Dept. of Posts w.e.f. 1.4.92. Condition of minimum three years service for certain categories of employees, like of local bodies etc. was removed.

To date, the PLI work of twelve Circles out of twenty (including APS) has been computerised.

Customer Satisfaction

During the year 1992-93, 717215 Public Complaints were received and enquired into as against 669950 complaints received in the year 1991-92. The percentage of complaints to the total traffic is thus 0.00531 against 0.00484 in the previous year.

Marketing and Commercial Publicity

The Universal Postal Union in its Washington Congress held in 1989, adopted what is known as the "Washington General Action Plan". The plan

emphasised the imperative need for Postal administrations to adopt effective market strategies. By now, almost all the Postal Administrations have realised the paramount importance of good Public Relations because they offer a key public utility service. The common phenomenon noticed everywhere was that ubiquitious Postal Services were taken for granted and public cooperation, which is essential for any organisation before it can render good quality service to customers at a reasonable cost, is not possible without good public relations and adequate public education.

Apart from creating a good image of the Department in the eyes of the customer and boosting the morale of the staff, the marketing effort also aims at eliciting cooperation from the customers in essential areas like correct and legible addressing, use of standard dimensioned stationery, timely posting of mail and use of Pin Code etc. Successful and proper marketing effort thus results in cost effectiveness - it reduces the number of handlings in the network - besides bringing about qualitative improvement in the service.

It was with this background that a comprehensive corporate image building plan was drawn up by the Marketing Division of the Directorate General of Posts. The Plan included campaigns in the press, disseminating messages for the customers to help the Department render a better service at a reduced cost, education through advertisements, establishment of Post Forums, holding of customers' Meets and Round Tables and the like. The Pin Code Week held during 18-24 January, 1993, was a positive step towards popularising Pin Code. The use of Pin Code is extremely necessary from the point of view of reducing handling costs in the systems as well as for optimum utilisation of automatic mail processing centres. The Postal Services Board has ordered broad-basing the activities of the Commercial Publicity Cell with a view to earning more revenue for the Department. Through commercial advertising on postal stationery, the Department realised in 1992-93, a revenue of Rs. 1.62 crores against a revenue of Rs. 1.30 crores in 1991-92. Domestic Speed Post traffic grew from 53 lakhs in 1991-92 to 73 lakhs in 1992-93. Similarly, while revenue in 1991-92 for domestic Speed Post was Rs. 22 crores, it rose to Rs. 32 crores in 1992-93. There has hardly been any product variation in Speed Post during the last year. It can, thus, be said that the traffic growth shall attribute to marketing efforts and better performance against the couriers.

Returned Letters

The Department's 15 Returned Letter Offices which process ultimately undelivered mail, handled 29.3 million pieces of mail during 1992-93; 57% of which were improved, re-addressed and delivered; 28% were returned to the senders after ascertaining their addresses.

Postal Premises

During the year 1992-93, the Department spent a sum of Rs. 37.20 crores on construction and allied activities. Out of this amount Rs. 25.17 crores have been spent on construction of various Post Offices and administrative buildings, Rs. 6.41 crores for staff quarters and Rs. 5.62 crores have been spent on acquisition of land. A sum of Rs. 30.88 lakhs was spent on building activities in Postal Training Centres.

During the year 1992-93, the Department completed construction of 98 Post Office buildings and other office buildings; 247 staff quarters were constructed; 12 ready-built staff quarters were purchased. Construction of 128 office buildings and 375 staff quarters commenced during the year.

The Department identified 32 of its historic buildings as 'Heritage Buildings'. Heads of Circles have been directed to pay special attention to their restoration. Indian National Trust for Art and Cultural Heritage has been appointed by the Department as consultant for the Mandi Head Post Office as well as for Bombay GPO, which completes 200 years of its existence in 1994 and Calcutta GPO which is in the midst of its 125th anniversary celebrations. INTACH, Archaeological Survey of India, and the School of Planning and Architecture, New Delhi, are involved in restoration and conservation of Calcutta GPO, Lucknow GPO and other heritage buildings. Certain important buildings like Bangalore GPO, Hyderabad Circle Office etc. have been declared "Special" buildings and are given special face lift and maintenance care.

POSTAL FINANCE

The total revenue during the year 1992-93 was Rs. 1073.90 crores, registering an increased receipt of Rs. 126.03 crores i.e. about 13.3%, against the preceding year's receipts of Rs. 947.87 crores. The revenue realised was 108.5% of the revenue estimated for the year. The increase was mainly because of better financial management rather than by revision of tarrif.

The net working expenses of the year were Rs. 1165.71 crores against the previous year's expenditure of Rs. 1162.15 Crores (i.e an increase of just about 0.3%). Expenditure of Rs. 1149.36 crores was projected in R.E. 1992-93. The increase was mainly due to increase in expenditure under pensionary charges on account of more retirements than anticipated. The revenue-expenditure gap of the postal services during 1992-93 was brought down to Rs. 91.81 crores as compared to Rs. 214.28 crores in 1991-92. This was also less by Rs. 67.55 crores against the estimated gap of Rs. 159.36 crores.

REVENUE AND EXPENDITURE 1992-93

(As compared to 1991-92)

(Rs. in crores)

Particulars	1991-92	1992-93	Percentage change over previous year
REVENUE			
Sale of Stamps	569.91	609.75	6.99
Postage realised in Cash	201.31	268.63	33.44
Commission on account of Money Orders, Indian Postal Orders, etc.	126.11	135.68	7.58
Other receipts	50.54	59.84	18.40
TOTAL	947.87	1073.90	13.29
EXPENDITURE			
General Administration	90.79	103.17	13.63
Operation	1042.76	1132.23	8.58
Agency Services	54.84	62.87	14.64
Others	318.36	350.91	10.22
Total Gross Expenditure	1506.75	1649.18	9.45
Less Recoveries	344.60	483.47	40.29
Net Expenditure	1162.15	1165.71	0.30

The Gross expenditure in important categories is given below :-

Particulars	1991-92	1992-93	percentage change over previous year
Pay & Allowances			
Contingencies & Other items	1106.22	1246.83	12.71
Pensionary charges	182.28	203.64	11.72
Audit & Accounts	33.30	37.65	13.06
Stamps & Postage etc.	38.81	45.77	17.93
Stationery & Printing etc.	25.74	18.50	(-)28.13
Maintenance of Assets	7.35	9.14	24.35
Depreciation	6.00	6.90	15.00
Petty Works	1.68	1.79	6.54
Conveyance of Mails (Payment to Railways & Airmail Carriers)	105.37	78.96	(-)25.06
TOTAL	1506.75	1649.18	9.45

POST CARD

LETTER

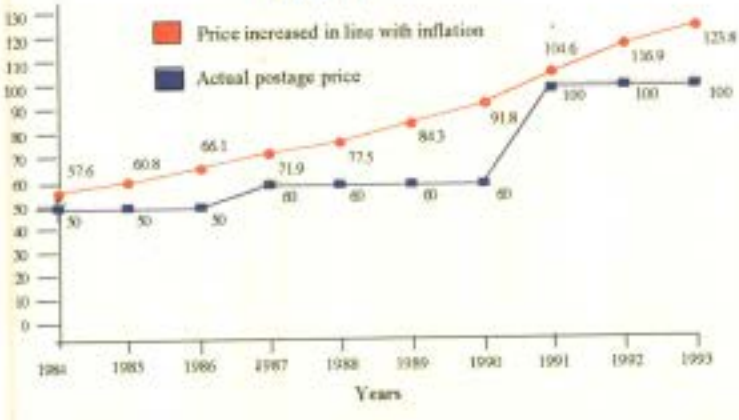

LETTERCARD

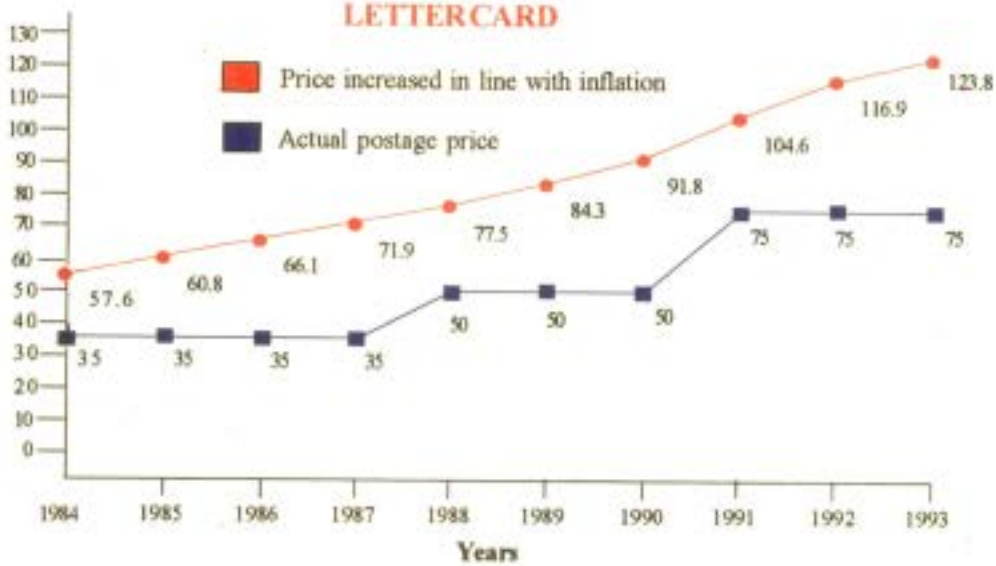

Revenue and Expenditure
(In Millions of Rupees)

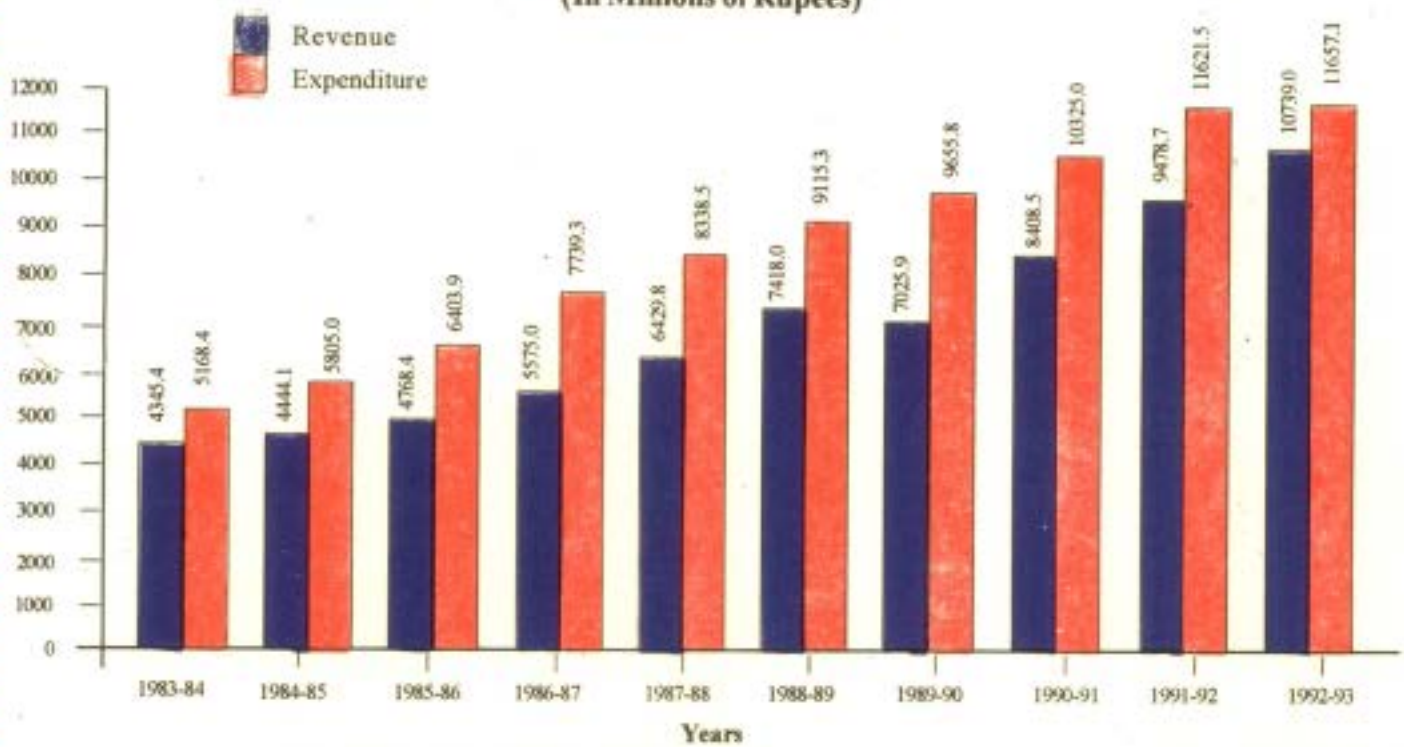

Cost of Service

The cost and revenue of main services for the year 1992-93 along with the position for the previous year are shown against each service below:

(Figures in Rupees)

Service	1991-92 Cost	1991-92 Revenue	1992-93 Cost	1992-93 Revenue
Postcard	1.25	0.15	1.54	0.15
Printed Card	1.20	0.60	1.44	0.60
Letter Card	1.41	0.75	1.57	0.75
Letter	1.43	1.81	1.78	1.85
Parcel	18.51	14.31	22.11	17.02
Money Order	13.16	8.99	14.09	10.97
Registration	8.76	6.00	10.36	6.00
Insurance	12.66	18.12	13.76	11.01
Book Post				
Book Pattern and Sample Packet	1.78	2.42	2.28	1.79
Printed Books	2.25	2.26	2.94	1.52
Others	2.47	2.11	3.27	1.29

Agency Services

In the year 1992-93, the Department's recovery of working expenses on account of agency services was as follows:-

(Rupees in crores)

Savings Bank & Savings Certificate	446.88
Postal Life Insurance	27.33
Payment of Railway Pension	1.15
Coal Miners'/EPF Pension	3.57
Customs Duty realisation	0.91
Military Pension	0.18
Others	3.45
Total	483.47

Capital Outlay

The gross outlay on fixed assets in the year was Rs. 55.21 crores. Of this 67.9% was on land and buildings and 32.1% on apparatus, plants and others. Capital outlay on fixed assets rose to Rs. 513.23 crores at the end of the year. The net progressive capital outlay to the end of the year financed from General Revenue was Rs. 419.52 crores.

HUMAN RESOURCES

Manpower

Personnel continued to be the principal resource for the Indian Postal System. The total staff strength as on 31.3.93 was 5.96 lakhs, including 3.06 lakhs Extra Departmental Employees who man most of the services in the rural areas.

Training Programmes

The training infrastructure of the Department of Posts consists of the following Training Institutes:-

Postal Staff College of India, Ghaziabad.

Posts & Telegraphs Training Centre, Saharanpur.

Postal Training Centres, Vadodara, Mysore, Darbhanga and Madurai.

The Postal Staff College of India at Ghaziabad is the apex training institute catering to the training needs of the managerial cadres of the Department of Posts. The main objective of this college is to impart induction and in-service training to the officers of the Indian Postal Service and P&T Accounts & Finance Service with a view to inculcating in them:

-requisite knowledge, skills and attitude to enable them to make the Postal System effective and responsive to the needs of the people.

-Providing leadership to vocational training of operative cadres through the Five Regional Training Centres.

-Undertaking research in the spheres of the management of the postal system;and

-building up a Postal Data Bank and Documentation Centres. In addition, work-shops on different aspects of the postal services at the request of the Universal Postal Union and other International Organisations are also organised for the benefit of officers belonging to Foreign Administrations.

During the period ending 31st March, 1993, five induction and nine in-service courses were conducted by the Postal Staff College of India. In all, 209 officers participated in these courses.

The main objectives of the Regional Postal Training Centres are:-

-to impart induction training to Time Scale Clerical recruits of Department of Posts.

-to impart in-service refresher training to Postal and Sorting Assistants, Supervisors, Inspectors, ASPOs, Postmasters etc.;and

-to train officers promoted to middle managerial positions and equip them to shoulder higher responsibilities with confidence and develop appropriate managerial knowledge and skills required for independent management of Postal and RMS Divisions.

Induction training in Postal and Telegraph services is also organised for officers belonging to Foreign Administrations at these Centres. A total number of 15,236 persons were imparted training during the period ending 31st March, 1993, at the five Regional Training Centres. Fifteen Officers belonging to the Postal Administration of the Royal Government of Bhutan underwent 8½ months induction training at PTTC, Saharanpur.

Postal Staff College

The foundation stone for Staff Quarters' complex was laid on 23.10.92. In all, 29 quarters (six Type-I, eight Type-II, six Type-III, two Type-IV, four Type-V, three Type-VI quarters) are under construction and are expected to be ready by May, 1994.

As an effort towards environmental improvement, 1000 saplings were planted in the campus during 1992-93. The campus has now a total of 2000

young trees; sprawling lawns and flower beds also enhance its landscape.

The College has all the necessary modern teaching aids and equipment for imparting high level training. Computerisation has been approved and is in progress. The Hostel with its well furnished rooms can accommodate 50 officers at a time. Games and recreational facilities, including billiards, are available on the premises.

Staff Relations

The Department maintains healthy and meaningful relations with the three Federations and 27 Unions/Associations of its Employees and Extra Departmental Agents.

During the period April, 1992 to March, 1993 two meetings of the Postal Departmental Council (JCM) were held. In addition, 28 meetings of its committees, four periodical meetings and six meetings of the Standing Committee, three meetings of the Departmental Committee on ED Agents were also held during the period. The main objective of the meetings with the Federations/Unions/Associations was to find amicable solutions to the various demands of the Employees and Extra Departmental Agents.

SC/ST Employees

Out of 80 cases of grievances/complaints of SC/ST employees, 60 cases were settled.

Internal Work Study

-Evolution of norms for Sub-Divisional Inspectors is in progress;

-The study relating to norms for supervisory posts in MMS has been completed.

The following studies have been approved by the Staff Inspection Unit (S.I.U), Ministry of Finance and are in the process of implementation:-

Sale of Indira Vikas Patra.

Fixing out turn of LDCs(SBCO) on the electronic adding and listing machines.

Booking of Speed Post articles.

Payment of Indira Vikas Patras.

Rationalisation of norms fixed by Madan Kishore Committee in respect of accounts branches of Head Post Offices/Head Record Offices.

The following work studies were completed:

Study relating to evolution of norms for providing clerical assistance to IPOs/ASPOs in Postal Sub-Division and Study relating to articles received in sorting and posted for despatch.

Recognition of Higher Performance

Meritorious service is always recognised by the Department and employees whose merit needs recognition at the national level, have been honoured with the Meghdoot Award. For the year 1992-93, the following Officials were recognised for their outstanding contribution to the Department and were awarded the Meghdoot Award:

Shri Raghubir Singh, EDBPM, Haryana Circle,

Shri M.G. Ramanna, Postman, Karnataka Circle,

Shri R. K. Saxena, Postal Assistant, U.P. Circle,

Shri R. Ravindran Pillai, Asst. Supdt. of Post Offices, Kerala Circle, and

Shri Dhian Singh, Mailguard, Punjab Circle.

Staff Welfare

The Postal Services Staff Welfare Board functions under the Chairmanship of the Minister of Communications. The objectives of the Board are to promote, develop, organise and exercise overall control in respect of staff amenities and welfare, sports and cultural activities in the Department. The Board

receives government grant-in-aid. Voluntary contribution from staff and collection through sports and cultural activities are arranged by the subordinate formations.

The funds of the Welfare Board are utilised for activities like sports, community centres, recreation clubs, relief in case of natural calamities, education scholarships, subsidy for excursion trips, and grants to help handicapped staff and children, vocational training centres, creches and schools.

Holiday Homes

The Department is running Holiday Homes at 19 locations for its employees and their families.

Sports

All India Postal Sports Board organised tournaments in Table Tennis (Indore), Weight Lifting, Power Lifting and Best Physique (Ambala), Badminton (Cuttack), Athletics and Cycling (Trivandrum), Kabaddi (Bombay), Wrestling (Jallandur) and Chess (Shimla) during the year.

Use of Hindi in Official Work

The Department, according to the policy of the Government of India, has been making concerted efforts to ensure maximum use of Hindi as the official language at the Headquarters and also in the subordinate offices. Official Language Implementation Committees have been constituted at the Directorate General, Circle Headquarters and their subordinate offices.

With a view to implementing the OL Act and Rules made thereunder, and compliance of Annual Programmes issued by the Department of Official Language, offices are inspected and remedial steps initiated to remove deficiencies.

The Committee of Parliament on Official Language visited 25 offices. Suggestions made by it were implemented.

In keeping with the policy to promote implementation of Hindi through incentives and goodwill, various incentive schemes have been introduced at the Headquarters and subordinate offices for progressive use of Hindi. These Schemes include Akhil Bhartiya Dak Rajbhasha Shield, Dak Vibhag Maulik Hindi Pustak Puraskar Yojna, Awards for writing original articles in Hindi in 'Dak Patrika', Dak Vibhag Rajbhasha Shield, Incentive for original noting and drafting in Hindi, Essay competition, Hindi Elocution competition and Hindi Quiz.

Part-2
Annual Report
1993-94

Mail Operations

Snow-bound areas of Himachal Pradesh - Lahaul, Udaipur and Kilar Pangi - isolated during winter will hence-forth be receiving all first-class mails on time by means of special air sorties, as a result of an agreement made with the Border Roads Organisation and the Ministry of Defence, thus solving a long pending problem of these areas.

Automatic Mail Processing Centre, Bombay

Automatic Mail Processing Centre has been commissioned in Bombay from 29th April, 1993. This technologically advanced system now effectively deals with 44 lakhs pieces of mail per day which works out to 9% of the daily all-India volume of mail. The mail is brought to 30 coding desks where after barcoding they are fed into two letter sorting machines programmed to sort simultaneously for 200 destinations each at a speed of 30,000 letters per hour.

Counter Mechanisation

Service at the counter has always been the focus of attention in the modernisation schemes of the Department. To ease the pressure represented by long queues during peak hours, the Department has placed orders for procurement, installation and commissioning of 1000 PC based Multi-Purpose Counter Machines under Annual Plan 1993-94. By December, 1993, 350 machines were commissioned.

Electronic Money Transfer via Satellite

The Department has a scheme for transmission of money order via satellite at 75 locations in the country. The proposal involves installation of PCs and VSAT (Very Small Apparatus Terminals). The pilot project is to be launched by March, 1994, at 5 locations - Delhi, Madras, Bangalore, Lucknow and Patna.

Induction of Mechanical Equipments

In order to improve the quality and legibility of postal cancellations, an order for the manufacture of 25,000 handstamps has been placed with the Ordnance Factories Organisation. 270 stamp cancelling machines are also being supplied to important Post Offices in the country so as to expedite stamping of inward and outward postal articles.

Expansion of Postal Network

519 EDBOs and 16 DSOs have been sanctioned up to 31.12.1993, as against the annual plan target of 600 EDBOs and 100 DSOs. The remaining 81 EDBOs and 84 DSOs will be sanctioned by 31.3.1994.

Philately

32 Commemorative/Special postage stamps were issued from 1.4.93 to 31.12.93. These issues included two sets of four stamps each on 'Mountain Locomotives' and 'Flowering Trees' which proved to be very popular with philatelists. Special stamps on Swami Vivekananda's Chicago address, Khan Abdul Gaffar Khan and golden jubilee of Indian National Army also attracted wide attention in the country.

Philatelic sale is managed all over the country through 50 philatelic bureaux and 174 philatelic counters. Seven State/ Circle level exhibitions were held from 1.4.93 to 31.12.93.

The National Philatelic Exhibition INPEX-93 was organised by the Department in Calcutta, from 25.12.93 to 29.12.93 with the cooperation of the Philatelic Congress of India. The Department also participated in the following international exhibitions where India postage stamps were displayed and sold:- INDOPEX-93 at Surabaya, Indonesia, held from 29.5.93 to

4.6.93.

BANGKOK-93 at Bangkok, Thailand, held from 1.10.93 to 10.10.93.

Universal Postal Union

Annual Sessions of the Executive Council of Universal Postal Union were held at Berne from 25.4.93 to 5.5.93 and the Consultative Council for Postal Studies from 10.10.93 to 27.10.93. Shri S.K. Parthasarathy, Secretary, Department of Posts, led the delegation at both the Sessions.

India was represented by a two member delegation at the Annual Session of Executive Council of the APPU and the Governing Board meeting of the APPU Training Centre held at Kobe, Japan, from 1.9.93 to 9.9.93.

SAARC

India, as Chairman of the SAARC Technical Committee on Communications, organised a workshop on "Mechanisation of Postal Operations", from April 12 to 23, 1993, and hosted the first meeting of the SAARC Technical Committee on Communications, May 24-25, 1993. An Indian delegation attended two courses under SAARC activities in Bangladesh, December 18 to 23,1993 on "Circulation System on EMS" and in Nepal on "Safety and Security of Postal Services", December 21 to 22, 1993. Postal Staff College, Ghaziabad, conducted a workshop on "Training for Trainers", from January 24 to February 11, 1994.

Bilateral Cooperation

The President of Uzbekistan during his visit to India reached an agreement on bilateral cooperation in the field of Posts and Allied Matters. It was signed by the Minister of State for Communications and the Uzbek Foreign Minister on 5.1.94.

A delegation of the Chinese Postal Administration accompanied the Chinese Vice Minister for Postal & Telecommunications to India. They met with their Indian counterparts on 23.11.93.

Shri S.R. Faruqi, Member (Development), represented India at the 10th Conference of Commonwealth Postal Administration held at Auckland, New Zealand from September 20 to 24, 1993.

Heads of Circles Conference, 1993

The Conference of Heads of Postal Circles was held at New Delhi on July 29 and 30, 1993. Minister of State for Communications inaugurated the Conference. The Minister stressed the importance of speedy delivery of mails. In pursuance of various suggestions made by the Minister in his inaugural address, the Conference took several important decisions in regard to handling of mails in metro cities and other matters.

Mahila Samriddhi Yojna, 1993

This new Scheme, aimed at economic empowerment of the rural woman, was launched from 1.10.93. In this Scheme an incentive of 25% per annum, subject to maximum of Rs. 75 per annum will be granted to the rural woman who makes a deposit under the scheme.

Postal Life Insurance

Important steps taken in this area include:-

1) The upper ceiling of non-medical scheme has been increased from Rs. 20,000/- to Rs. 1,00,000/-. Female lives, which were not hitherto covered, have now been included.
2) Grace period for payment of premium has been extended from 21 days to one calendar month.

Official Language

The O.L. Branch brought out a publication titled, "Dak Prashasan Sabdavali Evam Manak Masauda", which was distributed in the Directorate. The "Dak Vibhag Rajbhasha Shield" that includes cash awards, was given away by the Minister of State for Communications. A Hindi Workshop for officers of the level of Directors was organised for the first time in the Directorate. The Hindi Week was observed in the Directorate and subordinate offices from September, 14-20, 1993, during which programmes/competitions were organised and prizes awarded. The Department convened the 1st Rajbhasha Sammelan at Trivandrum, on January 19 and 20, 1994.

STATISTICAL SUPPLEMENTS

TABLE - 1

(Rupees in crores)

	Financial Working	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94 (B.E.)
1.	**RECEIPTS**	741.80	702.59	840.85	947.87	1073.90	1000.00
	EXPENDITURE						
2.	General Administration	72.91	80.25	83.28	90.79	103.17	108.63
3.	Operation	775.64	864.29	905.49	1042.76	1132.23	1136.63
4.	Agency Services	38.47	44.07	46.31	54.84	62.87	62.51
5.	Audit & Accounts	25.76	28.99	30.88	33.30	37.65	41.71
6.	Engineering Maintenance	14.50	16.24	11.48	18.54	21.51	26.60
7.	Amenities to Staff	11.30	11.51	10.67	11.77	12.90	16.07
8.	Pensionary Charges	99.89	110.18	150.31	182.28	203.64	204.00
9.	Stamps, Stationery & Printing	46.61	62.07	63.16	66.19	66.23	81.28
10.	Depreciation	4.87	5.19	5.40	6.00	6.90	8.00
11.	International Cooperation	0.66	0.76	1.09	0.08	1.81	2.59
12.	Social Security & Welfare Programmes	0.12	0.25	0.19	0.20	0.27	0.25
13.	Gross Working Expenses (Total of Items 2 to 12)	1090.73	1223.80	1308.26	1506.75	1649.18	1688.27
14.	Less-Credits to Working Expenses	179.20	258.22	275.76	344.60	483.47	550.00
15.	Net Working Expenses (Item 13 minus 14)	911.53	965.58	1032.50	1162.15	1165.71	1138.27
16.	Net Receipts (Item 1 minus 15)	(-) 169.73	(-) 262.99	(-) 191.65	(-) 214.28	(-) 91.81	(-) 138.27
17.	Dividend to General Revenues	-	-	-	-	-	-
18.	Surplus(+)/Deficit(-) (Item 16 plus 17)	(-) 169.73	(-) 262.99	(-) 191.65	(-) 214.28	(-) 91.81	(-) 138.27

TABLE - 2

Capital outlay during and upto the end of 1992-93

(Rupees in crores)

		During 1992-93	Upto the end of 1992-93
A.	**FIXED ASSETS**		
1.	Land	5.73	49.21
2	Building	31.77	410.63
3	Railways Mail Vans Owned by Post Offices	-	8.61
4	Apparatus and Plant	14.73	30.21
5	Motor Vehicle	2.98	14.03
6	Other Expenditure	-	0.54
7	Gross Fixed Assets	55.21	513.23
8	Deduct-Receipts and Recoveries on Capital Accounts	0.06	0.73
9	Deduct-Expenditure met from Posts & Telegraphs Capital Reserve Fund	-	1.29
10	Deduct-Amount of Contribution from Revenue	-	27.86
11	Deduct-Depreciation on historical cost transferred from Revenue	6.90	58.92
12	Total Deductions (i.e. total of Item 8 to 11)	6.96	88.80
13	Net Fixed Assets (i.e. Item 7 minus 12)	48.25	424.43
B	**OTHER ASSETS**		
14	Consumer Co-operative Societies Share Capital Contribution	-	-
15	Civil Engineering Suspense	(-) 1.53	(-) 4.91
16	Total Other Assets (Item 14 Plus 15)	(-) 1.53	(-) 4.91
17	Total Capital Outlay Financed from General Revenues (Item 13 Plus 16)	46.72	419.52
18	Deduct-Portion of Capital Outlay Financed from Ordinary Revenues	-	1.05
19	Total Capital Outlay (Voted) (i.e. Item 17 minus 18)	46.72	418.47

TABLE - 3

Number of Post Offices as on 31st March, 1993

S.No.	State/Union Territories	Urban	Rural	Total	Area served by a Post Office (Sq. Kms.)
	STATES				
1.	Andhra Pradesh	1396	14816	16212	16.96
2.	Assam	300	3480	3780	22.31
3.	Arunachal Pradesh	13	256	269	311.15
4.	Bihar	643	11058	11701	14.86
5.	Goa	57	187	244	15.15
6.	Gujarat	812	8072	8884	22.07
7.	Haryana	315	2250	2565	20.88
8.	Himachal Pradesh	111	2522	2633	21.41
9.	Jammu & Kashmir	201	1382	1583	140.23
10.	Karnataka	1332	8429	9761	19.64
11.	Kerala	691	4300	4991	7.81
12.	Madhya Pradesh	1093	10081	11174	50.42
13.	Maharashtra	1462	10699	12161	22.32
14.	Manipur	35	625	660	33.33
15.	Meghalaya	31	439	470	44.65
16.	Mizoram	39	323	362	58.00
17.	Nagaland	19	275	294	56.11
18.	Orissa	588	7438	8026	19.40
19.	Punjab	467	3363	3830	23.98
20.	Rajasthan	924	9333	10257	33.34
21.	Sikkim	7	163	170	41.75
22.	Tamil Nadu	1990	10095	12085	10.79
23.	Tripura	49	640	689	15.08
24.	Uttar Pradesh	2068	17868	19936	14.76
25.	West Bengal	1104	7342	8446	10.49
	UNION TERRITORIES				
1.	Andaman & Nicobar	17	80	97	84.53
2.	Chandigarh	43	6	49	2.41
3.	Delhi	434	116	550	2.54
4.	Dadra & Nagar Haveli	1	33	34	18.78
5.	Daman & Diu	4	11	15	21.01
6.	Lakshadweep	-	10	10	2.24
7.	Pondicherry	37	62	99	4.57
	Total	16283	135754	152037	21.6

TABLE - 4

SAVING BANK - Outstanding Balances

(Number in Lakhs)
(Amount in crores of Rupees)

	1988-89		1989-90		1990-91		1991-92		1992-93	
	No. of Account	Amount	No. of Account	Amount	No. of Account	Amount	No. of Account	Amount	No. of Account	Amount
Saving Bank	450	3564	476	3766	647	3976	466	4376	375	4590
CTD	57	499	67	383	83	270	77	202	77	108
Recurring Deposits	283	1850	334	2255	385	2638	414	3094	439	3631
Time Deposits	10	4987	10	3830	12	2973	14	2861	13	2717
National Saving Scheme	6	810	34	2516	30	4592	25	6755	26	7061
Monthly Income Scheme	3	792	13	1535	13	2340	11	2720	14	3348
Total	809	12502	934	14285	1170	16789	1007	20008	944	21455
Savings Certificates		21340		27515		33320		35756		38681
Grand Total		33842		41800		50109		55764		60136

TABLE - 5

Postal Life Insurance

Year	New Business		Total Business in force		Life Insurance Fund
	No. of Policy (in Lakhs)	Sum Assured (Rs. in crores)	No. of Policy (in Lakhs)	Sum Assured (Rs. in crores)	(Rs. in crores)
1983-84	1.17	143.0	10.84	809.4	223.9
1984-85	1.12	153.0	11.56	942.8	260.6
1985-86	1.01	160.4	12.16	1070.9	307.2
1986-87	1.03	179.3	12.81	1227.6	368.9
1987-88	1.20	232.9	13.62	1439.3	446.1
1988-89	1.37	294.9	14.58	1711.5	534.5
1989-90	1.63	432.5	15.79	2119.4	642.8
1990-91	1.56	476.3	16.92	2567.9	776.0
1991-92	1.60	558.5	18.04	3092.3	949.4
1992-93	1.51	576.8	19.00	3621.3	1134.4

TABLE - 6

PERSONNEL : Actual Strength (including those on deputation and training outside the department) as on 31.3.93.

A. GAZETTED	
Secretary (Posts)	1
Member, Postal Services Board	3
Secretary, Postal Services Board	1
Indian Postal Service	
Senior Deputy Director General/Chief Postmaster General	4
Senior Administrative Grade	82
Junior Administrative Grade	106
Time Scale	178
Postal Service Group 'B'	953
P&T Accounts & Finance Service	
Senior Administrative Grade	1
Junior Administrative Grade	9
Time Scale	17
Accounts Officers & Asstt. Accounts Officers	623
Central Secretariat Service	63
Civil Wing	
Chief Engineer	1
Others	236
Other General Central Services	201
Total	2479

Non Gazetted	Group 'C'	Group 'D'	Total
Directorate	466	158	624
Post Offices	198689	32424	231113
Railway Mail Service	26845	19331	46176
Mail Motor Service	2177	652	2829
Others	3817	2997	6814
Total	231994	55562	287556
Total Departmental			290035
B. EXTRA DEPARTMENTAL			306027
Grand Total (A+B)			596062

TABLE - 7

Number of Employees - Scheduled Castes/Tribes as on 31-3-1993

	Scheduled Castes	Percentage to Total No. of Employees	Scheduled Tribes	Percentage to Total No. of Employees
Group 'A'	82	12.85	27	4.23
Group 'B'	197	10.70	47	2.55
Group 'C'	42357	18.25	13511	5.82
Group 'D' (Excluding Sweepers)	10855	19.53	3357	6.04
Group 'D' (Sweepers)	916	75.20	148	12.15

TABLE - 8

Number of Employees - Ex-Servicemen as on 31-3-1993

	Ex-Servicemen	Disabled Ex-Servicemen
Group 'A'	-	-
Group 'B'	1	-
Group 'C'	2289	180
Group 'D'	603	45

The new Head Post Office
Olavakkot, Kerala

India National Philatelic Exhibition (INPEX-93)
Calcutta, December 1993